@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

साहस समाचार

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक

'पालकी पे होके सवार' गाने पर अंकिता लोखंडे ने किया रिवीलिंग डांस ... पेज-8

नई दिल्ली, मंगलवार, 16 दिसंबर 2025, वर्ष-1, अंक-53, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

मनरेगा अब होगी 'जी राम जी' योजना

नई दिल्ली, एजेंसी।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर नया कानून लाने के लिए प्रस्तावित विधेयक सोमवार को लोक सभा में पेश नहीं किया गया। 'विकसित भारत– रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन– ग्रामीण ' (विकसित भारत जी राम जी) विधेयक 2025 को लोक सभा की आज की पूरक कार्यसूची में शामिल किया गया था। राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील इस विधेयक को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सदन में पेश करना था लेकिन इसे पेश नहीं किया गया।

पूरक कार्यसूची में 'विकसित भारत जी राम जी' विधेयक तथा शिक्षा और परमाणु कानून में संशोधन सहित कुल चार विधेयक दर्ज थे जिनमें से तीन पेश कर दिये गये। वर्ष 2005 में पारित मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार को प्रति वर्ष न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी है। यह कानून तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक था। इसको प्रतिस्थापित करने के लिए लाये जा रहे नये विधेयक को शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।

इस विधेयक में 100 के स्थान पर न्यूनतम 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का प्रस्ताव है तथा खेती–बाड़ी में श्रमिकों की कमी की समस्या को ध्यान में रखते हुए बुवाई–कटाई के सीजन में इस योजना के तहत कामों को वर्ष में 60 दिन तक स्थगित रखा जा सकता है। यह फैसला राज्य सरकारों के हाथ में होगा कि किस समय इसे स्थगित रखना है। इसमें योजना को केंद्रीय क्षेत्र की जगह केंद्र प्रायोजित योजना बनाने का प्रावधान है और राज्यों को अंशदान करना होगा।

इसमें केंद्र तथा राज्य का अंशदान 60:40 के अनुपात में होगा । पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90 प्रतिशत धन केंद्र देगा। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है वहां पूरा खर्च केंद्र उठाएगा। मनरेगा के तहत अब भी राज्य सरकारें कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के खर्च में 25 प्रतिशत और प्रशासनिक में 50 प्रतिशत का योगदान कर रही हैं। इस विधेयक के बारे में सरकार की ओर से जारी प्रश्नोत्तरी में कहा गया है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख क्षेत्रों– जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना के विकास के कामों तथा अति वृष्टि या अनावृष्टि जैसी मौसम संबंधी आपादाओं के आजीविका पर प्रभाव को दूर करने के लिए विशेष कार्यों को संपादित किया जाएगा।

जम्मू: उधमपुर मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद

जम्मू, एजेंसी।

जम्मू–कश्मीर में उधमपुर जिले के जंगल से सटे एक दूरदराज के गांव में सोमवार शाम हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि माना जा रहा है कि एक आतंकवादी घायल हुआ है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, गोलीबारी भले ही रुक गई हो, लेकिन पूरे इलाके को कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया है। छिपे हुए आतंकवादियों को मार गिराने के लिए उनके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि यह मुठभेड़ पहाड़ी जिले के मजालता इलाके के सोअन गांव में तब शुरू हुई जब सुरक्षाबलों ने यहां तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर तलाशी अभियान संचालित किया। माना जाता है कि ये आतंकी पाकिस्तान स्थित जैश–ए–मोहम्मद संगठन से जुड़े हैं। जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) भीम सेन टूटी ने बताया कि दूरदराज के गांव में आतंकवादियों के बारे में सटीक सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों और आतंकवादियों का आमना–सामना हुआ।

सार समाचार

दिल्ली में कोहरे के कारण रद्द हुईं 228 उड़ानें, पांच डायवर्ट

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को घने कोहरे के कारण 228 उड़ानें रद्द हुईं और पांच को दूसरे शहरों के लिए डायवर्ट करना पड़ा। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने यूनीवार्ता को बताया कि आज दिल्ली से रवाना होने वाली 131 और दिल्ली आने वाली 97 उड़ानें रद्द रहीं। इसके अलावा सैकड़ों उड़ानों देरी हुई। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का समाना करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि आधी रात के बाद लगभग दो बजे से ही दिल्ली–एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ शहरों में कोहरा घना होने लगा। दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समय दृश्यता लगभग शून्य रह गयी थी।

संजय सरावगी बने बिहार प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय नेतृत्व ने सोमवार को दरभंगा शहरी सीट से विधायक संजय सरावगी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले शीर्ष नेतृत्व ने रविवार को बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके एक दिन पहले शनिवार को उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद पर केंद्र सरकार में राज्य मंत्री पंकज चौधरी को तैनात किया गया था।

अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे मेसी का हुआ भव्य स्वागत

नई दिल्ली,एजेंसी। अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनल मेसी, रोड्रिगो डी पॉल और लुइस सुआरेज का यहां सोमवार को भव्य स्वागत हुआ। जैसे ही फुटबॉल के दिग्गज मैदान पर उतरे, उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर और गर्मजोशी से मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान जोरदार तालियां बजीं, झंडे लहरा कर स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों ने उनका भव्य स्वागत किया गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने लियोनल मेसी को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी नंबर–10 भेंट की है, इस नंबर की जर्सी कभी सचिन तेंदुलकर पहना करते थे। n जर्सी पर मेसी का नाम लिखा हुआ था। जय शाह ने लुईस सुआरेज को जर्सी नंबर–9 और रोड्रिगो डि पॉल को जर्सी नंबर–7 दी। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहां मौजूद थी। प्रत्यक्षदर्शीयों ने बताया कि उनके आने की सूचना के कुछ ही मिनटों में स्टेडियम में मौजूद भीड़ ने खुशी से मेसी, मेसी का शोर मचाना शुरू कर दिया।

नितिन नबीन ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला

नई दिल्ली, एजेंसी।

नितिन नबीन ने सोमवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि नवीन के संगठनात्मक कौशल से जनसेवा और राष्ट्र निर्माण की पार्टी की यात्रा को एक नयी दिशा मिलेगी। भाजपा मुख्यालय में नवीन को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सम्मानित भी किया गया। नड्डा ने नवीन को पार्टी के अहम पद का कार्यभार संभालने की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनसेवा और राष्ट्र निर्माण की भाजपा की यात्रा को एक नयी दिशा प्रदान करेंगे।

उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, इसके साथ ही आप भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और संगठन के विचारों को और भी दृढ़ संकल्प के साथ जनता तक पहुंचाएंगे। मैं आपकी नयी जिम्मेदारियों और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वहीं, शाह ने नवीन को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा का और भी विस्तार होगा तथा वह मोदी सरकार की नीतियों एवं पार्टी की विचारधारा को देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, मैं ईश्वर से आपके सफल कार्यकाल के लिए प्रार्थना करता हूं। नबीन के आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद शाह, नड्डा और प्रधान ने उनके साथ चर्चा की।

आतंकवाद के खिलाफ जॉर्डन की सोच भारत जैसी: प्रधानमंत्री मोदी

अम्मान, एजेंसी।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जॉर्डन के शाह ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की, वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने सोमवार को यहां मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की तथा पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन आतंकवाद के खिलाफ साझा और स्पष्ट रुख रखते हैं। अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर मोदी दो दिवसीय यात्रा पर जॉर्डन पहुंचे। शाह ने मोदी का हुसैनीया पैलेस में गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता से पहले दोनों के बीच आमने–सामने की बैठक हुई।

दोनों पक्षों ने अपनी साझेदारी को और गहरा करने पर सहमति जताई, विशेष रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद–रोधी तथा कट्टरपंथ–उन्मूलन, उर्वरक एवं कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा तथा पर्यटन के क्षेत्रों में। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ अपने एकजुट रुख की पुनः पुष्टि की।

मोदी ने कहा, हमें उम्मीद है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम होगी। आतंकवाद के खिलाफ हमारी साझा और स्पष्ट सोच है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरपंथ के खिलाफ दुनिया को एक मजबूत और रणनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने क्षेत्र में स्थायी शांति हासिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के प्रति भारत के समर्थन की पुनः पुष्टि की। अब्दुल्ला द्वितीय ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति मजबूत समर्थन व्यक्त किया और सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरपंथ से निपटने में शाह अब्दुल्ला द्वितीय के नेतृत्व तथा इन बुराइयों के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में उनके योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने गाजा मुद्दे पर शाह अब्दुल्ला द्वितीय की सक्रिय और सकारात्मक भूमिका की सराहना की। मोदी ने याद किया कि 2018 में शाह अब्दुल्ला द्वितीय की भारत यात्रा के दौरान वह इस्लामी विरासत पर आयोजित एक सम्मेलन में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने शाह अब्दुल्ला द्वितीय से कहा, आपके प्रयास न केवल क्षेत्रीय शांति, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा, मुझे याद है कि हमारी पहली मुलाकात भी 2015 में संयुक्त राष्ट्र के इतर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जिसका जोर हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करने पर था। उस समय भी आपने इस विषय पर प्रेरणादायी विचार रखे थे। मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन इस दिशा में मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे तथा आपसी सहयोग के सभी अन्य आयामों को और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शाह अब्दुल्ला द्वितीय से कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनकी मुलाकात भारत–जॉर्डन संबंधों को नयी गति प्रदान करेगी और इससे उसमें प्रगाढ़ता आएगी।

उन्होंने कहा, हम व्यापार, उर्वरक, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग जारी रखेंगे। मोदी ने उनका और उनके प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए जॉर्डन के शाह का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आपने भारत–जॉर्डन संबंधों को नयी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बेहद सकारात्मक विचार साझा किए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने के मामले में माफी मांगें राहुल, खरगे: रीजीजू

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कथित रूप से दी गई धमकी के लिए माफी मांगनी चाहिए।

रीजीजू ने यहां आनन–फानन में बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को हुई कांग्रेस की रैली के दौरान पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की धमकी दी। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र में घटित हुई सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना बताया।

उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री को धमकी दिए जाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने की सार्वजनिक तौर पर धमकी दी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता एवं नेता राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, दुश्मन नहीं।

उन्होंने कहा, हम अलग–अलग विचारधाराओं का प्रचार करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सपने के अनुरूप विकसित भारत के लिए मिलकर काम करते हैं।

रीजीजू ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अलग विषय हैं और उनके बावजूद नेता सार्वजनिक रूप से एक–दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और वे विभिन्न तरीकों से एक–दूसरे की आलोचना भी करते हैं।

उन्होंने कहा, हम अलग–अलग तरीकों से एक–दूसरे का विरोध करते हैं। हम एक–दूसरे को जान से मारने के बारे में कभी नहीं सोचते और न ही ऐसी बात करते हैं। यह कैसी मानसिकता है? यह कैसी प्रवृत्ति है कि कुछ लोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जान से मारने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं? रीजीजू ने कहा कि मोदी 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करती है, पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करता है लेकिन यदि विपक्ष में कुछ लोग प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देते हैं तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। इस घटना की केवल निंदा कर देने से बात समाप्त नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष (खरगे) और विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) को संसद में माफी मांगनी चाहिए। उन्हें संसद के पटल पर देश से माफी मांगनी चाहिए। रीजीजू ने कहा कि यदि कांग्रेस में अब भी मानवता शेष है और वह देश की जनता का सम्मान करती है तो उसे संसद के दोनों सदनों में तत्काल माफी मांगनी चाहिए।

श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के नेता वेदांती नहीं रहे

अयोध्या,एजेंसी।

श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी नेता रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद राम विलास वेदांती का हृदयाघात के कारण सोमवार को मध्यप्रदेश के रीवा स्थित एक अस्पताल में निधन हो गया। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि वेदांती लंबे समय से बीमार थे और सोमवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। वेदांती 67 वर्ष के थे। वेदांती के शिष्य छोटे दास महाराज ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार अयोध्या में किया जाएगा। वेदांती के उत्तराधिकारी महंत राघवेश दास ने बताया कि पूर्व सांसद के पार्थिव शरीर को आज अयोध्या लाया जा रहा है।

रीवा स्थित श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के अधीक्षक अक्षय श्रीवास्तव ने कहा कि वेदांती को रविवार सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

शीर्ष अदालत ने कहा, एक ओर जहां कानून अप्रभावी है और इसलिए दहेज की कुप्रथा व्यापक रूप से जारी है

दहेज-विरोधी कानून अप्रभावी और दुरुपयोग का शिकार: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि दहेज प्रथा का उन्मूलन एक अत्यावश्यक संवैधानिक और सामाजिक आवश्यकता है। साथ ही रेखांकित किया कि मौजूदा कानून 'अप्रभावी' और 'दुरुपयोग' दोनों से ग्रस्त हैं, और यह बुराई अब भी व्यापक रूप से प्रचलित है।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन.. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस मुद्दे से निपटने के लिए सभी के 'सामूहिक प्रयास' की आवश्यकता पर जोर देते हुए उच्च न्यायालयों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304–बी और 498–ए के तहत लंबित मामलों की संख्या (सबसे पुराने से लेकर सबसे नए तक) का पता लगाने सहित कई निर्देश जारी किये ताकि उनका शीघ्र निपटान किया जा सके।

पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की धारा 304–बी दहेज हत्या से संबंधित है, वहीं धारा 498–ए पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा विवाहित महिला से क्रूरता सें संबंधित है।

पीठ ने दहेज हत्या के 24 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र और राज्यों को सभी स्तरों पर शैक्षिक पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलावों पर विचार करने का निर्देश दिया, साथ ही इस संवैधानिक स्थिति को मजबूत करने का भी निर्देश दिया कि विवाह के दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हैं और कोई भी दूसरे के अधीन नहीं है। पीठ ने कहा कि यह मामला दर्शाता है कि दहेज प्रथा केवल हिंदुओं में ही नहीं पाई जाती, बल्कि यह अन्य समुदायों में भी प्रचलित है जो विभिन्न धर्मों और आस्थाओं को मानते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा, एक ओर जहां कानून अप्रभावी है और इसलिए दहेज की कुप्रथा व्यापक रूप से जारी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय दंड संहिता की धारा–498 ए के साथ–साथ इस अधिनियम (दहेज निषेध अधिनियम) के प्रावधानों का इस्तेमाल गुप्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी किया गया है।''

पीठ ने कहा, अप्रभाविता और दुरुपयोग के बीच यह उतार–चढ़ाव एक न्यायिक रूप से असहज स्थिति पैदा करता है जिसका तत्काल समाधान करने की जरूरत है।

उच्चतम न्यायालय का यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुनाया, जिसमें 2001 के दहेज हत्या मामले में एक महिला सहित दो व्यक्तियों को बरी कर दिया गया था।

शीर्ष अदालत ने अपीलें स्वीकार कर लीं और मामले में उनकी दोषसिद्धि को बहाल कर दिया। हालांकि, अदालत ने 94 वर्षीय महिला दोषी को कारावास की सजा नहीं दी।

अदालत ने दोषी व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पीठ ने कि हालांकि इस मामले में आरोपियों को आखिरकार सजा मिल गई है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ऐसा नहीं होता है।

शीर्ष अदालत ने कहा, कई लोग खुलेआम दहेज मांगते और देते हैं, वे बिना किसी सजा के बच जाते हैं। विभिन्न न्यायिक निर्णयों में बार–बार यह बात सामने आई है कि दहेज निषेध अधिनियम (डीपीए), (1961) के कार्यान्वयन में कई कठिनाइयां हैं। कई निर्देश पारित करते हुए पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को दहेज की कुप्रथा और इससे बचने की आवश्यकता के बारे में सूचित और जागरूक किया जाए। फैसले में कहा गया, इस प्रकार, यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य और यहां तक कि केंद्र सरकार भी सभी स्तरों पर शैक्षिक पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलावों पर विचार करें।

दिल्ली में प्रदूषण के चलते पांचवीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी

नई दिल्ली, एजेंसी।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को स्कूलों को कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए 'हाइब्रिड मोड' से 'ऑनलाइन मोड' में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर–सरकारी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए प्रत्यक्ष कक्षाएं अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं।

दिल्ली में मौजूदा उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के कारण यह निर्णय लिया गया है। स्कूल को निर्देश दिया गया है कि इन विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं केवल ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएं। हालांकि, शिक्षा विभाग द्वारा 13 दिसंबर को जारी निर्देशों के अनुसार, शेष कक्षाएं 'हाइब्रिड मोड' में संचालित की जाएंगी। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार को 427 के साथ 'गंभीर' श्रेणी में रहा। रविवार को यह 461 के साथ दिसंबर माह के दूसरे सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार को दिल्ली के 27 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'गंभीर' थी, जिनमें से 12 केंद्र पर गुणवत्ता 'अत्यंत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई।

गुरुग्राम को सुव्यवस्थित, नागरिक अनुकूल शहर बनाना प्राथमिकता: राव नरबीर सिंह

गुरुग्राम को जाम व जलभराव से राहत दिलाने के लिए मंत्री राव नरबीर ने किया निरीक्षण।

गुरुग्राम,एजेंसी।

गुरुग्राम शहर को यातायात जाम एवं जलभराव की समस्या से स्थायी समाधान दिलाने के उद्देश्य से हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने सोमवार को शहर के विभिन्न हिस्सों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत हीरो होंडा चौक से करते हुए कैबिनेट मंत्री ने फ्लाईओवर की मरम्मत कार्यों, मेट्रो निर्माण से पूर्व तैयारियों तथा यातायात प्रबंधन की समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले वाहन डायवर्जन एवं विस्तृत मोबिलिटी प्लान तैयार किया जाए, ताकि आमजन को न्यूनतम असुविधा हो और ट्रैफिक सुचारु बना रहे। इसके उपरांत राव नरबीर सिंह ने उमंग भारद्वाज चौक से गाड़ौली गांव तक सडक़ मार्ग का निरीक्षण किया। राव ने अधिकारियों से बैठक करके स्पष्ट कहा कि सडक़ निर्माण से पूर्व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी की जाए।

गांव गाड़ौली में बादशाहपुर ड्रेन का निरीक्षण करते हुए कैबिनेट मंत्री ने ड्रेन को पक्का करने तथा उसकी नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी औद्योगिक इकाई का प्रदूषित पानी ड्रेन में न छोड़ा जाए।

इस संबंध में नियमित निगरानी की जाए। शहर में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री ने सेक्टर-9 स्थित ग्रीनवुड स्कूल के निकट, सेक्टर-7 एवं 9 चौक, पालम विहार में बजघेड़ा फ्लाईओवर से पहले कृष्णा चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों को पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रमुख चौक-चौराहों पर स्लिप रोड के निर्माण के निर्देश दिए।

राव ने कहा कि गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित होते शहर में भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। कैबिनेट मंत्री ने सेक्टर-10 में प्रस्तावित मेट्रो मार्ग का भी निरीक्षण किया। मार्ग में मौजूद अतिक्रमण, भूमिगत एवं ऊपरी सुविधाओं के शिफ्टिंग प्लान तथा निर्माण से जुड़ी तकनीकी तैयारियों की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने निर्देश दिए कि मेट्रो परियोजना के दौरान यातायात और नागरिक सुविधाओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़े, यह सुनिश्चित किया जाए।

सेक्टर-22 स्थित ताऊ देवीलाल पार्क के सामने के मार्ग का निरीक्षण करते हुए उद्योग मंत्री ने राव नरबीर सिंह ने जीएमडीए एवं जीएमआरएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो निर्माण अथवा ड्रेन चौड़ीकरण कार्य शुरू करने से पहले ट्रैफिक मूवमेंट के लिए पर्याप्त चौड़ाई वाला वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित किया जाए। मंत्री राव नरबीर सिंह ने ताऊ देवीलाल पार्क की मौजूदा सुविधाओं का जायजा लेकर पार्क के सौंदर्यीकरण, हरियाली बढ़ाने तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए सीएसआर फंड के उपयोग के निर्देश दिए। दौरे के अंतिम चरण में कैबिनेट मंत्री ने एयर फोर्स स्टेशन के सामने चल रहे ड्रेन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।

द्वारका, मुंबई एक्सप्रेसवे, एनएच-48 पर यातायात पुलिस की सख्त नजर

गुरुग्राम,एजेंसी।

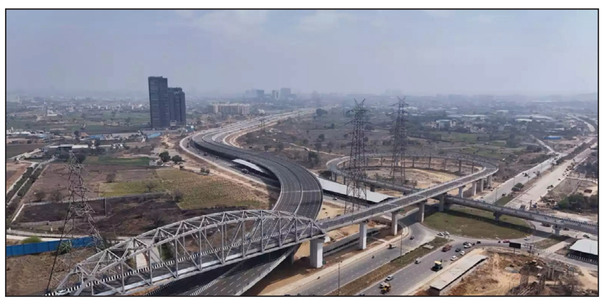

द्वारका एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 (एनएच-48) पर यातायात पुलिस गुरुग्राम ने सख्ती बढ़ा दी है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के यातायात पुलिस धड़ाधड़ चालान काट रही है। एक सप्ताह में यहां की यातायात पुलिस ने 17,584 वाहनों के चालान करके एक करोड़ 61 लाख 96 हजार 400 रुपये का जुर्माना ठोंका। पुलिस उपायुक्त यातायात गुरुग्राम डा. राजेश मोहन द्वारा यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरुक करने के लिए हैशटैग चालान नहीं सलाम मिलेगा अभियान के तहत लगातार छठे माह में आठ दिसंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा 17,584 चालान किए गए।

इनमें मैदानी स्तर पर किए गए 12,297 चालान शामिल है, जिनमें रॉन्ग साइड ड्राइविंग 1607, रोड मार्किंग 735, पिलियन राइडर बिना हेल्मेट 895, बिना सीट बेल्ट 984, ड्राइवर बिना हेल्मेट 870, ड्रंकन ड्राइविंग 271, रॉंग पार्किंग 922, डेंजरस यू-टर्न 358, ट्रिपल राइडिंग 159, ओवरस्पीड 114, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग 96, ध्वनि प्रदूषण 40, लेन चेंज 584 तथा कैमरों के माध्यम से 5287 चालान किए गए। जिनमें नो एंट्री 316, ओवर स्पीडिंग 2747, लेन चेंज 1951, ड्राइवर बिना हेल्मेट 12, पिलियन राइडर बिना हेल्मेट 06, ड्राइवर बिना सीट बेल्ट 200, ट्रिपल राइडिंग 02 तथा फ्रंट पैसेंजर बिना सीट बेल्ट 53 चालान शामिल है। इस अवधि के दौरान मैदानी स्तर पर किए चालानो से कुल एक करोड़ 61 लाख 96 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

सडक़ अनुशासन बनाए रखने एवं सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा एनएच-48, द्वारका एक्सप्रेसवे तथा मुंबई एक्सप्रेसवे पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन की सहायता से लेन चेंज और ओवरस्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ निरंतर चालान की कार्रवाई की गई। विशेष रूप से एनएच-48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर लेन चेंज के 1951 चालान किए गए, जो सडक़ सुरक्षा व अनुशासन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त कदम है।

फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किशोरी से दुष्कर्म

लोनी,एजेंसी।

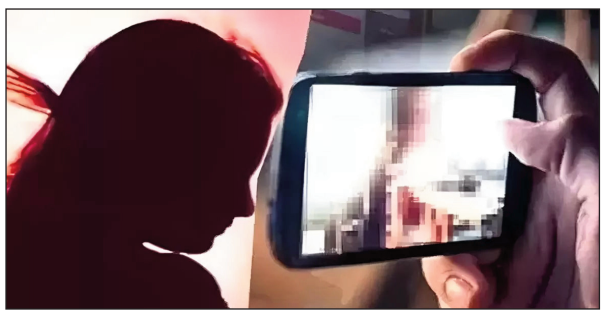

ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी किशोरी के अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने पुलिस आयुक्त को शिकायत देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति की 16 वर्षीय पुत्री एक वर्ष पहले घर से बिना बताए चली गई थी। मामले में परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी थी। अगले दिन किशोरी घर लौट आई।

घर आने के बाद किशोरी ने परिजनों को बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मारपीट कर अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। साथ ही किसी को कुछ बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। लोक लाज के चलते युवती और परिजनों ने कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि चार दिसंबर रात में आरोपी युवक घर आया और पुत्री को डरा धमका कर अपने साथ ले गया। पुत्री के घर पर दिखाई न देने पर परिजन उसे तलाशते हुए आरोपी के घर पहुंचे। परिजन किशोरी को वहां से घर ले आए, घर आने के बाद पुत्री ने बताया कि युवक ने दोबारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

परिजनों ने अगले दिन मामले की सूचना पुलिस को दी। पता चलने पर युवक ने किशोरी और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। जिस पर पीड़िता के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त से कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

अवैध कब्जा किए बैठे दो बदमाशों से मुक्त कराई सरकारी जमीन

गुरुग्राम,एजेंसी।

खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा करके उन्हें कमाई का जरिये बनाने के दो अपराधियों पर नगर निगम का बुल्डोजर चला। कब्जा की गई जमीनों को छोडऩे के बदले या तो वे पैसे लेते थे या फिर वहां पर किसी को दुकान आदि चलाने की एवज में वसूली करते थे। सोमवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम गुरुग्राम की ओर से उनके अवैध निर्माणों को ढहाकर जमीन को खाली करवाया गया।

जानकारी के अनुसार बादशाहपुर के रविदास मोहल्ला निवासी रवि पुत्र शेर सिंह ने नगर निगम गुरुग्राम की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। वह बादशाहपुर शमशान घाट के सामने नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करके उसका व्यवसायिक उपयोग कर रहा था। यह कब्जा खसरा नंबर 39/24 की भूमि पर किया गया था। पिछले करीब पांच साल से उसने यह अवैध कब्जा कर रखा था। सोमवार को नगर निगम गुरुग्राम की टीम पूरी तैयारी के साथ उसके द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंची।

इस दौरान सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई। नगर निगम के बुल्डोजर से सभी निर्माणों को ढहाकर सरकारी जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया गया।मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी रवि के खिलाफ बादशाहपुर पुलिस थाना में कई केस दर्ज हैं। उसका काफी गंभीर अपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ आम्र्स एक्स, एक्साइज एक्ट समेत कई धाराओं में पांच एफआईआर दर्ज हैं। बताया गया कि आरोपी का हिंसक प्रवृत्ति का इतिहास रहा है। उसका संबंध टिल्लू गैंग से पाया गया है।

आरोपी रवि एक आदतन अपराधी एवं गैंग सदस्य है। पूर्व में आरोपी/सह-आरोपी न्यायिक हिरासत में होने के कारण उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था।दूसरे आरोपी नरेंद्र द्वारा भी किए गए अवैध कब्जों को ढहाया गया। आरोपी का नाम नरेंद्र उर्फ टिल्लू पुत्र शेर सिंह है। यह आरोपी रवि का भाई है। आरोपी नरेंद्र द्वारा भी नगर निगम गुरुग्राम की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। यह संपत्ति भी उसी जगह पर थी।

नरेंद्र द्वारा इस संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उसे किराये पर दिया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी नरेंद्र उर्फ टिल्लू के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। नरेंद्र का भी संबंध टिल्लू गैंग से इस आरोपी का संबंध भी टिल्लू गैंग से बताया गया है। नरेंद्र के खिलाफ बादशाहपुर पुलिस थाना में 11 केस, खेडक़ीदौला थाना में एक केस व गुरुग्राम के सेक्टर-17-18 थाना में एक केस दर्ज है। पुलिस आंकलन एवं जोखिम श्रेणी से उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी का अपराधिक प्रोफाइल हाई रिस्क श्रेणी में आती है। वह एक गैंग में सक्रिय, हिंसक प्रवृत्ति वाला आदतन अपराधी है।

अनिर्बन दिल्ली फुटबॉल टीम के सह प्रशिक्षक बने

नोएडा,एजेंसी।

शहर के अनिर्बन बरुआ दिल्ली सीनियर टीम के सहायक प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं। उन्हें संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वह दिल्ली महिला टीम के भी सहायक प्रशिक्षक रह चुके हैं। 17 दिसंबर से रांची में होने वाली प्रतियोगिता के लिए दिल्ली की टीम अलग-अलग स्थानों पर अभ्यास किया है। सेक्टर-11 निवासी अनिर्बन बरुआ पहले राष्ट्रीय स्तर की आई लीग फुटबॉल में खिलाड़ी के रूप में भाग ले चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रतियोगिताओं में भी दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने एनआईएस से डिप्लोमा भी किया है। प्रशिक्षक के लिहाज से उन्होंने डी और सी लाइसेंस भी प्राप्त किया है। वर्तमान में वह एक निजी स्कूल में खेल प्रमुख हैं।

बिग बिटर्स ने दर्ज कर पीसीके कप अपने नाम किया

फरीदाबाद,एजेंसी।

गांव भूपानी स्थित रावल क्रिकेट मैदान पर 79वें पीसीके कप के फाइनल मुकाबले में बिग बिटर्स ने द ए टीम के खिलाफ आठ विकेट से जीत दर्ज की। 20 ओवर के मुकाबले में द ए टीम बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवर में 128 रन पर आलआउट हो गई। पवन शर्मा ने 35, सिद्धार्थ ने 32 और तुषार ने 14 रन बनाए। बिग बिटर्स की ओर से रोहित चंदीला ने चार, रोहित शर्मा ने दो और राहुल व अर्जुन ने एक-एक विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए बिग बिटर्स ने दो विकेट के नुकसान पर 10.1 ओवर में 129 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया।खुशी गौतम ने 101 रन बनाए।द ए टीम की ओर से दुष्यंत व अंशु ने एक-एक विकेट लिया।खुश गौतम को मैन ऑफ द मैच व मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इनके अलावा मनोज को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, जितिन बत्रा को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज घोषित किया गया।

ईस्टर्न पेरिफेरल पर टकराए 10 से ज्यादा वाहन

ग्रेटर नोएडा,एजेंसी।

एनसीआर में लगातार बढ़ते घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ गया है। ऐसे हालात में पुलिस लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे को देखते हुए दादरी कोतवाली की कोट चौकी पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतते हुए वाहन चालकों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। एनएच-91 पर दादरी कोट चौकी पुलिस द्वारा लगातार हाईवे पर गश्त की जा रही है।

पुलिसकर्मी घने कोहरे के बीच हाईवे पर मौजूद रहकर अनाउंसमेंट के माध्यम से वाहन चालकों को जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों से विपरीत दिशा में वाहन न चलाने, तेज रफ्तार से बचने और निर्धारित लेन में ही चलने की सख्त सलाह दे रही है। इसके साथ ही वाहन चालकों से फॉग लाइट का प्रयोग करने, वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने और अनावश्यक ओवरटेक न करने की अपील की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

इसी बीच ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। ग्राम दादूपुर के सामने चलते ट्रक में पीछे से आ रहे कई वाहन आपस में टकरा गए, जिससे एक दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और सड़कों पर आलू बिखर गए, जिससे यातायात और भी बाधित हो गया।

ओखला पक्षी विहार प्रवासी पक्षियों से गुलजार

नोएडा,एजेंसी।

तापमान में गिरावट के साथ ही ओखला पक्षी विहार प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो गया। यहां नार्दन शेवलर, कॉमन कूट, ब्लैक हेडेड आईबिस समेत कई प्रजातियों के पक्षियों ने दस्तक दी है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार दिसंबर अंत तक और जनवरी में पक्षियों की संख्या और अधिक बढ़ेगी। फॉरेस्ट रेंजर अमित गुप्ता ने बताया कि लगभग सात हजार प्रवासी पक्षी ओखला पक्षी विहार में पहुंचे हैं। इनमें नॉर्दन शेवलर, कॉमन कूट, ब्लैक हेडेड आईबिस, कोरमोरेंट, कॉमन टील और ग्रेलेग गूज शामिल हैं।

ग्रेटर फ्लैमिंगों अभी पक्षी विहार में नहीं दिखा है। संभव है कि आने वाले समय में यह पक्षी भी यहां पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इन पक्षियों को झील में विचरण करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए जलकुंभी की सफाई की गई है। बांस के चबूतरे बनाए गए हैं, ताकि पक्षी आराम से बैठ सकें। प्रकृति प्रेमी दूर-दूर से इन खास पक्षियों को देखने और उनके नजारों का लुत्फ उठाने आते हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर नवंबर से शुरू होकर मार्च तक, जब ठंड बढ़ती है, तब ये पक्षी यहां आते हैं और फिर वापस अपने ठंडे इलाकों में लौट जाते हैं। ज्यादातर पक्षी तिब्बत, यूरोप, साइबेरिया, कनाडा और मध्य एशिया के ठंडे क्षेत्रों से आते हैं।

ठंड बढ़ने के साथ ही ओखला पक्षी विहार के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। वन विभाग के अनुसार पक्षी विहार खुलने का समय सुबह 7.30 बजे और बंद होने का वक्त शाम पांच बजे कर दिया गया है। अप्रैल तक यह समय लागू रहेगा। मई में गर्मियों का समय लागू कर दिया जाएगा। गर्मियों में ओखला पक्षी विहार सुबह सात बजे और बंद होने का वक्त शाम 5.30 बजे होता है।

अमित गुप्ता ने कहा कि ओखला पक्षी विहार में छह ई कार्ट हैं। इनमें लोगों की संख्या के अनुसार इन्हें चलाया जाता है। इन दिनों दो से तीन ई कार्ट चलाए जा रहे हैं। इनका एक तरफ का किराया 20 रुपये और दोनों तरफ का किराया 30 रुपये है। दो ई कार्ट सूरजपुर वेटलैंड भेजे गए हैं ओखला पक्षी विहार में देशी और प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या में प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इनमें ग्रेटर फ्लैमिंगो, पेलिकन, सारस, बगुले, बत्तख, किंगफिशर, और दुर्लभ प्रजातियां जैसे ब्लैक-बेलिड टर्न और काली गर्दन वाला सारस आदि शामिल हैं।

महिलाएं अपने आप में एक मजबूत शक्ति हैं: संगीता दास

गुरुग्राम,एजेंसी।

महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सुरक्षा को लेकर गुरुग्राम पुलिस की पहल तथा समाजसेविका मधु के सहयोग, समन्वय से सेक्टर-18 स्थित सरहौल स्थित अंबेडकर भवन में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में महिलाओं को सुरक्षित, आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला की मुख्य वक्ता के रूप में एडुटेनमेंट कुटुंब एनजीओ की अध्यक्ष संगीता दास रहीं। उन्होंने नारी सशक्तिकरण, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार पर अपने प्रेरणादायक विचार सांझा किये। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने आप में एक मजबूत शक्ति हैं। उन्होंने महिलाओं को आत्मबल, आत्मसम्मान और जागरूकता के महत्व से अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से एक सुरक्षित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर समाज की दिशा में यह एक सार्थक पहल सिद्ध हुई। यह कार्यशाला महिलाओं के लिए ज्ञान, संवाद और सशक्तिकरण का प्रभावी मंच बनी।

कार्यक्रम में महिला थाना पश्चिम गुरुग्राम से उप-निरीक्षक पूनम एवं मुख्य आरक्षी मोनिका ने महिला सुरक्षा कानूनों, हेल्पलाइन सेवाओं तथा पुलिस सहायता तंत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महिलाओं को किसी भी स्थिति में निडर होकर सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस नारी सशक्तिकरण एवं सुरक्षा कार्यशाला के दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों, आत्मरक्षा के उपायों, साइबर सुरक्षा तथा आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की।

जेसी बोस विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विदेशों में बढ़ेगी नौकरी के अवसर

फरीदाबाद,एजेंसी।

जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए के छात्रों के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर बढ़ेगें। इसे लेकर विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की नई मैच्योरिटी-बेस्ड ग्रेडेड एक्रेडिटेशन व्यवस्था के तहत तैयारी शुरू कर दी है। कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार ने सभी शैक्षणिक विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे नई प्रणाली के अनुसार अपने-अपने विभागों का स्व-विश्लेषण करें और जरूरी दस्तावेजों को समय पर तैयार करें। दरअसल, नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल यूजीसी की स्वायत्त संस्था है। जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन और एक्रीडिटेशन करती है।

यह काउंसिल शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, प्रशासन, छात्रों के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई मापदंडों पर संस्थानों का मूल्यांकन करती है। इसके लिए संस्थानों को 0 से 4.0 के स्केल पर ए, ए प्लस, ए प्लस प्लस ग्रेड दिए जाते हैं। इसी आधार पर अभी जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ए प्लस ग्रेडिंग मिली हुई है। हाल ही में काउंसिल ने इसमें मापदंडों में बदलाव किए हैं। मैच्योरिटी-बेस्ड ग्रेडेड एक्रेडिटेशन की एक नई प्रणाली है जो संस्थानों को उनके गुणवत्ता मानकों और प्रक्रियाओं में परिपक्वता के आधार पर स्तर 1 से 5 तक ग्रेड देती है, ताकि उनमें निरंतर सुधार हो, न कि सिर्फ मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त नहीं का वर्गीकरण होगा।

छात्रों को क्या होगा लाभ नई नैक व्यवस्था के तहत गुणवत्ता सुधार से पढ़ाई, शोध और प्रशिक्षण का स्तर बेहतर होगा। स्किल आधारित पाठ्यक्रमों और आरपीएल से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विदेशों में संस्थान की डिग्री के आधार नौकरियों के अवसर बढ़ेगे। गैर-इंजीनियरिंग छात्रों के लिए विशेष प्लेसमेंट पहल से सभी को समान मौके मिलेंगे।

उद्योग सहयोग से व्यावहारिक ज्ञान बढ़ेगा, वहीं बेहतर रैंकिंग से डिग्री की राष्ट्रीय पहचान और मूल्य मजबूत होगा। विश्वविद्यालय स्किल यूनिवर्सिटीज श्रेणी में भाग लेने की करें तैयारी कुलगुरु ने निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय एनआईआरएफ रैंकिंग की स्किल यूनिवर्सिटीज श्रेणी में भाग लेने की तैयारी करें। इसके साथ ही रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) पाठ्यक्रमों को तेजी से विस्तार देने पर जोर दिया गया। वर्तमान में स्कोडा इंडस्ट्रीज के साथ चल रहे सफल सहयोग को आगे बढ़ाते हुए नए उद्योगों के साथ भी समझौते करने के निर्देश दिए गए।

स्कूल पर प्री प्राइमरी के बाद कक्षा एक में प्रमोट नहीं करने का आरोप

गाजियाबाद,एजेंसी।

गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने बृज विहार स्थित एक स्कूल पर बच्चों को प्री प्राइमरी के बाद कक्षा एक में प्रमोट नहीं करने का आरोप लगाया है। जीपीए का कहना है कि स्कूल ने इसके लिए कम उम्र का हवाला दिया है, जबकि इससे पहले स्कूल कक्षा एक में दाखिले का आश्वासन देता रहा। इस संबंध में बीएसए को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रभावित अभिभावकों का कहना है कि इसी स्कूल में प्री और प्री-प्राइमरी की पढ़ाई के बाद बच्चों पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जा रहा है।

बच्चों को एक नई कक्षा बालवाटिका-3 में रोका जा रहा है। इसके पीछे स्कूल ने कम उम्र का हवाला दिया है, जबकि दाखिले के वक्त स्कूल ने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी थी। अपने लाभ के लिए स्कूल ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। कई अभिभावकों का यह भी कहना है कि स्कूल में लंबे समय से निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, सुरक्षा और मानसिक शांति प्रभावित हो रही है। ऐसे माहौल में बच्चों को जबरन एक अतिरिक्त वर्ष रोकना गलत है।

बीएसए से कार्रवाई की मांग: मामले में कार्रवाई के लिए गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन एवं अभिभावकों ने सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया। अभिभावकों की मांग है कि वर्ष 2024 में प्रवेश के समय जो शैक्षणिक क्रम तय किया गया था, उसी आधार पर बच्चों को सत्र 2026-27 में कक्षा एक में प्रमोट किया जाए। साथ ही बच्चों की शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाए। इस दौरान अनिल सिंह,पवन शर्मा, कौशलेंद्र, कौशल, नरेश, नवीन, राहुल, धर्मेंद्र, त्रिशान, राधिका, भावना, अमरेश, आयुष, पार्थ, गगनदीप सुमित आदि मौजूद रहे। अभिभावकों ने पहली क्लास में बच्चों को दाखिला नहीं देने की शिकायत की है। स्कूल से बात कर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। नियमों के मुताबिक कार्रवाई होगी।

RNI.No DLHIN/25/A2841
स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मै. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।
संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508
मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com
संपादक देवेंद्र सिंह तोमर
इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

'ऑपरेशन चक्रव्यूह' में पकड़े 24,000 से ज़्यादा ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले

दिल्ली पुलिस ने पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के निर्देश पर एक दिसंबर को यह अभियान शुरू किया था।

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अभियान 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के दौरान 24,000 से ज़्यादा गाड़ियों का चालान किया और 144 गाड़ियों को ज़ब्त किया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के निर्देश पर एक दिसंबर को यह अभियान शुरू किया था। ट्रैफिक प्रबंधन विभाग ने यह दो हफ़्ते तक चलने वाला अभियान स्थानीय पुलिस स्टेशनों और पीसीआर इकाइयों के साथ मिलकर चलाया। ट्रैफिक प्रबंधन के पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने कहा, इस अभियान में शहर भर के पहचाने गये हॉटस्पॉट पर बार-बार और गंभीर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर ध्यान दिया गया।

अभियान की रणनीति के तहत, ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस कर्मियों को रोज़ाना दो घंटे के लिये बहु-स्तरीय संरचनाओं में तैनात किया गया। इससे व्यस्त चौराहों, बाज़ारों और दुर्घटना संभावित इलाकों जैसे चुनिंदा स्थानों पर सभी प्रवेश और निकासी की जगहों को प्रभावी ढंग से सील कर दिया गया। जायसवाल ने कहा, इससे यह सुनिश्चित हुआ कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले कार्रवाई से बच न सकें।

आंकड़ों के अनुसार, इस कार्रवाई में कुल 24,841 चालान जारी किये गये। इस दौरान बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले, तीन लोगों के साथ दो-पहिया वाहन चलाने वाले, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले, लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गयी। अधिकारियों ने गंभीर अपराधों के लिये 144 गाड़ियां भी ज़ब्त कीं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां गाड़ियां चोरी की पाई गयीं।

अभियान के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी के अंदर नशीले पदार्थ भी बरामद किये, जिसके बाद तिमारपुर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गयी। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन चक्रव्यूह को कानून का पालन करने वाले नागरिकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। लोगों ने कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा कि इस अभियान ने सड़क अनुशासन में सुधार करने और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रदूषण पर तुलना नहीं, समाधान करे भाजपा सरकार: देवेन्द्र यादव

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो चुकी है, जहां 40 में से 39 एक्यूआई स्टेशनों पर स्तर 401 से ऊपर रेड जोन में दर्ज किया गया है, इसके बावजूद भाजपा सरकार दिल्ली की सांसों को बचाने के बजाय तुलनात्मक आंकड़ों का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को साल का सबसे अधिक एक्यूआई दर्ज हुआ, लेकिन सरकार को जनता के स्वास्थ्य की नहीं, बल्कि अपने रिपोर्ट कार्ड की चिंता है।

देवेन्द्र यादव ने अंतरराष्ट्रीय और सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कई इलाकों में एक्यूआई 600 से 1000 के बीच पहुंच चुका है और औसत स्तर भी बेहद खतरनाक स्थिति में है, जो भाजपा सरकार की प्रदूषण नियंत्रण नीतियों की विफलता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि गंभीर प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, अस्थमा, हृदय रोग, कैंसर और मानसिक तनाव जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी पुष्टि अस्पतालों और विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है।

देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले किए गए वादों के उलट भाजपा सरकार अब संकट के समय जिम्मेदारी से भाग रही है और रोज नई घोषणाएं कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब ग्रेप-4 लागू होने के बावजूद प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा और लोग दिल्ली छोड़ने को मजबूर हैं, तो इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार जिम्मेदार है और दिल्ली के तीन करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।

अब स्कूलों में आर्थिक पिछड़े वर्ग के दाखिले की तैयारी शुरू

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में सामान्य सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। अब शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों में आर्थिक पिछड़े वर्ग-वंचित वर्ग के ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया की तैयारी भी शुरू कर दी है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपशिक्षा अधिकारियों से स्कूलों की सही जीपीएस लोकेशन व सीटों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इसके लिए उन्हें 20 दिसंबर तक का समय दिया गया है।

इस साल इन वर्गों के बच्चों के लिए आवेदन प्रक्रिया फरवरी तक शुरू हो सकती है। इससे पहले दाखिला संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। बीते सालों की तरह ही दाखिले ऑनलाइन होंगे। शिक्षा निदेशालय में निजी स्कूल शाखा के उपशिक्षा शिक्षा निदेशक राजपाल सिंह की ओर से सभी जिला उपशिक्षा निदेशकों को एक परिपत्र जारी किया गया है। इसमें उन्हें निर्देशित किया गया है कि वह निजी स्कूलों के संबंध में सभी जानकारी व उनकी सूची 20 दिसंबर तक उपलब्ध कराएं। इसके लिए एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है जिसमें उन्हें सभी जानकारी देनी है।

इसमें उन्हें बताने को कहा गया है कि स्कूल में सामान्य, आर्थिक पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग व विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए कुल कितनी सीटें हैं। इन वर्गों की कितनी सीटें बीते साल बची और इन्हें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दाखिले के लिए जोड़ा गया है। इसे अलग-अलग वर्ग के हिसाब से बताने को कहा गया है। वहीं, स्कूलों की सही जीपीएस लोकेशन भी उपलब्ध करानी होगी जिसमें स्कूल के अक्षांश (लेटेट्यूट) व देशांतर (लांगिट्यूड) का पता चल सके। इससे बच्चे के सीट आवंटन में दिक्कत नहीं आएगी।

साथ ही सूची में जो नए स्कूल जुड़े हों या फिर स्कूल किसी दूसरे परिसर में शिफ्ट हुआ हो, उसकी जानकारी देनी होगी। इससे ऑनलाइन दाखिले के समय अभिभावकों को स्कूल का चयन करने में दिक्कत नहीं आएगी। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी जिला उपशिक्षा अधिकारी तय तिथि तक हर हाल में जानकारी उपलब्ध करा दें, जिससे कि समय से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा सके। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में आर्थिक पिछड़े वर्ग (ईडब्लयूएस) व वंचित वर्ग(डीजी), दिव्यांग श्रेणी की 25 फीसदी सीटों निर्धारित हैं। इन वर्गों के दाखिले सेंट्रलाइज्ड होते हैं और ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चे को स्कूल का आवंटन किया जाता है।

नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से भाजपा को मिलेगी नई ऊर्जा: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली,साहस समाचार।

भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने और उनके प्रथम दिल्ली आगमन पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व अन्य पार्टी नेताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत व अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि श्री नितिन नबीन का संगठनात्मक अनुभव, कर्मठ कार्यशैली और कार्यकर्ताओं के साथ सतत संवाद भाजपा संगठन को और अधिक सशक्त, अनुशासित तथा गतिशील दिशा प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्व पर श्री नितिन नबीन की नियुक्ति पार्टी नेतृत्व का युवा नेतृत्व पर विश्वास और भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके मार्गदर्शन में संगठनात्मक संरचना को नई ऊर्जा मिलेगी, साथ ही कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नितिन नबीन का राजनीतिक जीवन संगठनात्मक संघर्ष, अनुशासन और निरंतर सक्रियता का उदाहरण रहा है।

बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले नितिन नबीन ने छात्र राजनीति से लेकर संगठन के विभिन्न दायित्वों का सफल निर्वहन किया है। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता है, जो जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करते हैं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में विश्वास रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा आयु में राष्ट्रीय स्तर की यह जिम्मेदारी संभालना न केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि भाजपा भविष्य के नेतृत्व के निर्माण को लेकर गंभीर और दूरदर्शी है।

पार्टी के भीतर यह व्यापक विश्वास है कि श्री नितिन नबीन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और उन्हें संगठनात्मक कार्यों में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वे स्वयं बिहार गई थीं और नितिन नबीन के साथ चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से शामिल रहीं। उन्होंने कहा कि उस दौरान उन्होंने श्री नितिन नबीन की कार्यशैली, जनसंपर्क और संगठनात्मक पकड़ को नजदीक से देखा, जो पार्टी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें नेतृत्व के अवसर देने के पक्षधर रहे हैं। नितिन नबीन की नियुक्ति भी उसी सोच का प्रतिबिंब मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना रहा है कि युवा नेतृत्व नई सोच, नई ऊर्जा और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ संगठन और देश को आगे ले जाने में सक्षम होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और शीर्ष नेतृत्व के विश्वास के साथ नितिन नबीन निश्चित रूप से पार्टी संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उनका अनुभव, ऊर्जा और संवाद आधारित कार्यशैली आने वाले समय में पार्टी संगठन को और अधिक संगठित एवं मजबूत बनाएगी।

शोएब और नसीर की एनआईए हिरासत चार दिन बढ़ी

नई दिल्ली,साहस समाचार।

लालकिले के पास धमाके से जुड़े मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को आरोपी शोएब और डॉक्टर नसीर बिलाल मल्ला की एनआईए हिरासत चार दिन और बढ़ा दी। दोनों आरोपियों को कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। फरीदाबाद निवासी शोएब की दस दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं, जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के रहने वाले डॉक्टर नसीर बिलाल की सात दिन की हिरासत भी सोमवार को समाप्त हो गई थी।

एनआईए की मांग पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की कोर्ट ने हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। यह मामला 10 नवंबर को लालकिले के पास हुए धमाके से जुड़ा है। एनआईए का आरोप है कि शोएब ने उमर-उन-नबी को हमले से पहले ठिकाना और अन्य लॉजिस्टिक मदद दी थी। वहीं, डॉक्टर नसीर पर भी उमर को शरण देने, उसे सहायता पहुंचाने और हमले से जुड़े सबूत नष्ट करने का आरोप है। एनआईए के अनुसार, नसीर इस मामले में गिरफ्तार आठवां आरोपी है।

पंकज कुमार बने जेजेडी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष

नई दिल्ली,साहस समाचार।

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव द्वारा पार्टी जेजेडी के दिल्ली एनसीआर अध्यक्ष के पद पर पंकज कुमार को नियुक्त किया गया। पंकज कुमार को जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) द्वारा दिल्ली एनसीआर का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने उन्हें यह महत्वपूर्ण पदभार सौंपा है। पार्टी नेतृत्व के इस निर्णय से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।इस अवसर पर पंकज कुमार ने कहा कि पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का वे पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे तथा संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में सतत प्रयास करेंगे।

दक्षिण दिल्ली के गांवों में विकास कार्यों को मिली गति

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दक्षिण दिल्ली के गांवों में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने क्षेत्रीय विधायकों के साथ मिलकर आयानगर, महरौली, डेरा गांव और तुगलकाबाद में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। डेरा गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विधायक श्री करतार सिंह तंवर तथा नगर निगम की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष सुन्दर सिंह तंवर के साथ मिलकर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से निर्मित दो बारात घरों का उद्घाटन किया। इनमें से एक बारात घर सैन समाज के लिए विशेष रूप से बनाया गया है।

इसी अवसर पर उन्होंने विधायक करतार सिंह तंवर के साथ जननायक श्रद्धेय श्री कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत आयानगर में लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। यह उद्घाटन विधायक करतार सिंह तंवर के साथ संयुक्त रूप से किया गया। वहीं महरौली गांव में भी पांच करोड़ रुपये की लागत से सड़कों के निर्माण कार्य की शुरुआत विधायक गजेंद्र यादव की उपस्थिति में की गई। इसके अतिरिक्त तुगलकाबाद गांव में लगभग पचासी लाख रुपये की लागत से सड़कों और नालियों के निर्माण एवं सुधार कार्यों की भी आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं से गांवों में यातायात सुविधा बेहतर होने के साथ-साथ जल निकासी की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।

भागीरथ पैलेस में कई दवा फर्मों पर छापेमारी

नई दिल्ली,साहस समाचार।

अवैध, नकली और मिलावटी दवाओं के कारोबार के खिलाफ दिल्ली सरकार ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने भागीरथ पैलेस क्षेत्र में विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाकर कई दवा फर्मों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। इस विशेष अभियान के तहत औषधि नियंत्रण विभाग की टीमों ने भागीरथ पैलेस में संचालित थोक दवा विक्रेताओं के कुल 27 प्रतिष्ठानों की गहन जांच की। जांच के दौरान 10 से अधिक दवा फर्में औषधि नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं।

इन फर्मों के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। निरीक्षण के दौरान निर्धारित गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन को परखने के लिए सिरप, दवाइयों, रूई तथा अन्य शल्य चिकित्सा सामग्री के लगभग 204 नमूने एकत्र किए गए। इन सभी नमूनों को परीक्षण एवं विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है, ताकि दवाओं की गुणवत्ता और शुद्धता की पुष्टि की जा सके।

अभियान के दौरान एक दुकान पर बिना वैध लाइसेंस के चिकित्सा उपकरण एवं शल्य सामग्री की बिक्री करते हुए पाए जाने पर मामला दर्ज किया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित प्रतिष्ठान चिकित्सा उपकरण नियमों का उल्लंघन कर रहा था। विभाग द्वारा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जा रही है।

इससे पूर्व एक अन्य कार्रवाई में औषधि नियंत्रण विभाग और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने सदर बाजार के तेलीवाड़ा क्षेत्र में एक दवा व्यापारिक प्रतिष्ठान पर देर रात छापा मारा था। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के साइबर प्रकोष्ठ से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली और मिलावटी दवाएं तथा एंटी-फंगल क्रीम की खेप बरामद की गई थी।

जांच में पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठान बिना वैध औषधि लाइसेंस के संचालित हो रहा था और संचालक किसी भी प्रकार का वैध खरीद-बिक्री रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। भौतिक सत्यापन में बिक्री एवं वितरण के लिए रखे गए नकली ब्रांडेड बाह्य उपयोग की दवाओं का भारी भंडार भी सामने आया। प्रारंभिक जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जब्त की गई नकली दवाओं की आपूर्ति आसपास के राज्यों और पड़ोसी देशों तक की जा रही थी। इस गंभीर तथ्य को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्यों के औषधि नियंत्रण विभागों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है, ताकि समन्वित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

नमो भारत स्टेशन पर पसंदीदा पुस्तक भी खरीद सकेंगे

नई दिल्ली,साहस समाचार।

नमो भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्री अब स्टेशन पर ही अपनी पसंदीदा कहानी, किस्से की पुस्तकें भी खरीद सकेंगे। एनसीआरटीसी ने बुकटेल्स के साथ मिलकर आनंद विहार स्टेशन पर पुस्तक मेला शुरू किया है। 21 दिसंबर तक चलने वाले स्टोरी बॉक्स नाम के इस मेले में लोग सुबह 10 से रात 10 बजे तक किताबें खरीद सकेंगे। इस पुस्तक मेले की खास बात यह है कि इसमें बॉक्स-आधारित खरीदारी का विकल्प भी मौजूद है। लोग अलग-अलग किताबें खरीदने के बजाय एक बॉक्स भरकर किताबें चुन सकते हैं और इकट्ठा खरीद सकते हैं। इसके लिए दो अलग-अलग बॉक्स साइज के विकल्प उपलब्ध हैं।

यात्री अपनी पसंद और बजट के हिसाब से कोई भी बॉक्स चुनकर, उसमें जितनी किताबें आराम से फिट हो सकें, उतनी भर सकते हैं और पूरे बॉक्स की तय कीमत पर एक साथ खरीद सकते हैं। किताबें खरीदने का ये अनोखा तरीका, लोगों की जेब पर बिना बोझ डाले, उन्हें अलग-अलग तरह की किताबें चुनने और अपनी सभी पसंदीदा किताबें एक ही बार में खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। एनसीआरटीसी के अधिकारी ने बताया कि इस पुस्तक मेले में अलग-अलग तरह की किताबों का कलेक्शन मौजूद है। इनमें फिक्शन, नॉन-फिक्शन, बच्चों की किताबें और नए व युवा लेखकों की किताबें शामिल हैं। इसके अलावा युवा पाठकों के लिए एक खास सेक्शन भी बनाया गया है।

बारडोली भारत की नैतिक चेतना का प्रतीक: विजेन्द्र गुप्ता

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने गुजरात के बारडोली स्थित स्वराज आश्रम में आयोजित 14वीं सरदार संगोष्ठी एवं उत्तमचंद शाह स्मृति व्याख्यान को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। यह आयोजन राष्ट्रनिर्माता सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं तथा स्वतंत्रता सेनानी उत्तमचंद शाह की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संपन्न हुआ। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बारडोली केवल एक ऐतिहासिक स्थान नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नैतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि यहीं पहली बार अहिंसा, सामाजिक सुधार और जनसाहस की सामूहिक परीक्षा हुई, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। कार्यक्रम में लोकभारती ग्रामीण नवाचार विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रख्यात लेखक डॉ. विशाल भदानी, विचारक एवं लेखक तथा वरिष्ठ प्रशासक वसंत गडवी सहित अनेक प्रतिष्ठित वक्ता उपस्थित रहे। पूज्य मोरारीबापू की गरिमामयी उपस्थिति और आशीर्वचनों ने आयोजन को आध्यात्मिक ऊँचाई प्रदान की। दिल्ली विधान सभा के सदस्य अशोक गोयल, गजेन्द्र सिंह यादव, संदीप शेरावत तथा स्वराज आश्रम न्यास की सचिव निरंजनाबेन कलार्थी भी इस अवसर पर मौजूद रहीं।

माननीय अध्यक्ष श्री गुप्ता ने वीर विठ्ठलभाई पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में बारडोली की भूमिका केवल 1928 के प्रसिद्ध सत्याग्रह तक सीमित नहीं रही, बल्कि इससे पहले भी यह क्षेत्र राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र रहा है। उन्होंने 29 जनवरी 1922 की ऐतिहासिक जनसभा का उल्लेख करते हुए बताया कि महात्मा गांधी की उपस्थिति और वीर विठ्ठलभाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में हजारों खादीधारी लोगों ने भाग लेकर संगठित और अनुशासित जनआंदोलन का उदाहरण प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1922 में बारडोली में पारित प्रस्ताव असाधारण नैतिक साहस के प्रतीक थे। महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित कठोर शर्तों— अस्पृश्यता का उन्मूलन, सार्वजनिक संसाधनों तक समान पहुँच और अहिंसा के प्रति अटूट निष्ठा—को जनता ने स्वेच्छा से स्वीकार किया। इसी कारण बारडोली सामाजिक सुधार और राजनीतिक प्रतिरोध की प्रयोगभूमि बन सका।

अध्यक्ष ने कहा कि चौरी-चौरा की घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन भले ही स्थगित हो गया हो, परंतु बारडोली एक सिद्धांतनिष्ठ और अहिंसक जनआंदोलन के केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। यही परंपरा 1928 के बारडोली सत्याग्रह में अपने शिखर पर पहुँची, जब अन्यायपूर्ण लगान वृद्धि के विरोध में किसानों ने संगठित संघर्ष किया। सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन की सफलता के बाद जनता ने उन्हें "सरदार" की उपाधि प्रदान की।

दिल्ली में 11 इलाकों की हवा बेहद जहरीली

नई दिल्ली,साहस समाचार।

प्रदूषण के चलते लगातार तीसरे दिन राजधानी गैस चैंबर जैसी बनी रही। खासतौर पर सुबह और शाम के समय कोहरे के साथ मिलकर स्मॉग लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। सोमवार को दिल्ली के 11 स्थानों पर प्रदूषण का स्तर सीवियर प्लस यानी बेहद गंभीर श्रेणी में रहा। इन इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से ऊपर दर्ज किया गया। दिल्ली के लोगों को इस समय साल के सबसे ज्यादा भयावह प्रदूषित दिनों का सामना करना पड़ रहा है। हवा में मौजूद नमी के साथ मिलकर दिल्ली के वायुमंडल में स्मॉग बन रहा है, जिसके चलते लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर हो रहा है।

प्रदूषण के चलते लोगों को खांसी, छींक, नाक और गले में खराश, आंखों में जलन, सिरदर्द जैसी परेशानियां हो रही हैं। खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों और सड़क के किनारे रहने या सड़क के किनारे ज्यादातर समय बिताने वालों को इसकी परेशानी ज्यादा हो रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 427 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 461 के अंक पर रहा था।

यानी 24 घंटे के अंदर सूचकांक में 34 अंकों का सुधार हुआ है। हवा एकदम शांत पड़ जाने के चलते रविवार को दिल्ली का सूचकांक समग्र तौर पर सीवियर प्लस श्रेणी में चला गया था। लेकिन, सोमवार को हवा की गति थोड़ी बढ़ी। खासतौर पर दिन के समय धूप भी निकली और हवा की गति भी कुछ समय के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। इसके चलते प्रदूषण के स्तर में कुछ अंकों का सुधार हुआ है। सुबह दस बजे के लगभग दिल्ली का सूचकांक 450 के अंक पर रहा था। जबकि, शाम चार बजे तक इसमें और सुधार हुआ और यह 427 के अंत तक पहुंच गया। हालांकि, अभी भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में ही है।

जबकि, दिल्ली के 11 इलाकों का सूचकांक 450 से ऊपर यानी बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। मानकों से चार गुना ज्यादा सीपीसीबी के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। दिल्ली-एनसीआर की हवा में सोमवार दिन में तीन बजे पीएम 10 का औसत स्तर 388.7 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 261 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर अभी मानकों से लगभग चार गुना ज्यादा बना हुआ है।

संपादकीय

भाजपा का नितिन नबीन दांव: संगठन, संकेत और सियासी संदेश

भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से आने वाले युवा नेता नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपकर एक ऐसा निर्णय लिया है, जिसे केवल एक संगठनात्मक फेरबदल भर मान लेना राजनीतिक दृष्टि से भूल होगी। यह फैसला समय, परिस्थिति और आने वाले चुनावी संकेतों के संदर्भ में गहरे अर्थ रखता है। भाजपा का यह कदम बताता है कि पार्टी अब केवल सत्ता प्रबंधन नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति की बिसात भी सधे हुए तरीके से बिछा रही है। नितिन नबीन का राजनीतिक सफर भाजपा के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पार्टी पिछले कुछ वर्षों से आगे लाने का प्रयास कर रही है यानी युवा, अपेक्षाकृत स्वच्छ छवि वाले, जमीनी राजनीति से जुड़े और संगठन में लंबे समय से काम कर रहे नेता। बिहार जैसे राज्य से उनका आना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। यह प्रदेश लंबे समय से भाजपा की रणनीतिक प्राथमिकताओं में रहा है, जहां जातीय समीकरण, सामाजिक संतुलन और गठबंधन राजनीति हर निर्णय को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। ऐसे में बिहार से किसी नेता को राष्ट्रीय स्तर की संगठनात्मक जिम्मेदारी देना केवल सम्मान नहीं, बल्कि राजनीतिक निवेश भी है।

भाजपा के इस फैसले को पीढ़ीगत बदलाव के रूप में भी देखा जाना चाहिए। पार्टी नेतृत्व यह समझ चुका है कि आने वाले दशक की राजनीति केवल करिश्माई चेहरों या पुराने दिग्गजों के भरोसे नहीं चलाई जा सकती। संगठन को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो नई पीढ़ी से संवाद कर सकें, डिजिटल युग की राजनीति को समझें और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ विश्वसनीय संबंध बना सकें। नितिन नवीन की नियुक्ति इसी सोच का विस्तार प्रतीत होती है, जहां अनुभव और ऊर्जा के संतुलन पर जोर दिया गया है।

यह निर्णय एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है भाजपा का फोकस अब केवल केंद्र तक सीमित नहीं है। पार्टी राष्ट्रीय संगठन में राज्यों की भूमिका को लगातार बढ़ा रही है, खासकर उन राज्यों की, जहां राजनीतिक संघर्ष तीखा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में भाजपा अब केवल विस्तार नहीं, बल्कि स्थायित्व चाहती है। नितिन नवीन की जिम्मेदारी इस बात का संकेत है कि पार्टी बिहार और पूर्वी भारत को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने की रणनीति पर काम कर रही है।

विपक्ष के संदर्भ में देखें तो यह फैसला उन्हें एक स्पष्ट चुनौती देता है। जहां कई विपक्षी दल नेतृत्व संकट, अंदरूनी कलह और उम्रदराज नेतृत्व की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं भाजपा संगठित ढंग से नई नेतृत्व पंक्ति तैयार कर रही है। नितिन नवीन जैसे नेताओं को राष्ट्रीय मंच पर लाना यह दर्शाता है कि भाजपा केवल आज की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले कई चुनावी चक्रों की तैयारी कर रही है। यह दीर्घकालिक दृष्टि भाजपा को अन्य दलों से अलग खड़ा करती है।

हालांकि, यह नियुक्ति चुनौतियों से मुक्त नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद केवल औपचारिक नहीं, बल्कि अत्यंत सक्रिय भूमिका की मांग करता है। संगठन के भीतर विभिन्न गुटों, वरिष्ठ नेताओं की अपेक्षाओं और राज्यों की अलग-अलग राजनीतिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। नितिन नबीन के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वे खुद को केवल एक "चयनित चेहरा" नहीं, बल्कि प्रभावी संगठनकर्ता के रूप में स्थापित कर पाते हैं या नहीं। इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या भाजपा इस तरह की नियुक्तियों के जरिए सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना पाएगी। अतीत में कई बार यह देखा गया है कि संगठनात्मक पदों पर नई पीढ़ी को लाने के बावजूद वास्तविक निर्णय प्रक्रिया पुराने शक्ति केंद्रों के पास ही रहती है। यदि नितिन नवीन को वास्तविक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी मिलती है, तो यह प्रयोग सफल हो सकता है; अन्यथा यह केवल प्रतीकात्मक नियुक्ति बनकर रह जाएगी। फिर भी, कुल मिलाकर भाजपा का यह निर्णय राजनीतिक रूप से सधा हुआ और दूरदर्शी प्रतीत होता है। नितिन नबीन की नियुक्ति न केवल युवा नेतृत्व को प्रोत्साहन देती है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि भाजपा क्षेत्रीय संतुलन, संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की राजनीति तीनों को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है।

भाजपा में युवा नेतृत्व की नई आहट पर भरोसा

ललित गर्ग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का एक स्थायी गुण रहा है- नए चेहरों पर भरोसा और पीढ़ीगत नेतृत्व का निर्माण। चाहे वह केंद्र सरकार में मंत्रियों का चयन हो, राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हो या संगठन में बदलाव- मोदी ने बार-बार यह साबित किया है कि वे भविष्य की राजनीति को आज गढ़ने में विश्वास रखते हैं।

भारतीय राजनीति में लंबे समय से जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, वह अब एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की बागडोर युवा हाथों में सौंपने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नितिन नबीन को पार्टी का नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। यद्यपि यह नियुक्ति औपचारिक रूप से अस्थायी कही जा रही है, किंतु जिस प्रकार से इस निर्णय का पार्टी के भीतर और बाहर स्वागत हो रहा है, उससे यह संकेत स्पष्ट हैं कि भविष्य में उन्हें ही पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। यह नियुक्ति केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की कार्यशैली, नेतृत्व-चयन और भविष्य-दृष्टि में आए एक बड़े परिवर्तन का उद्घोष है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड का यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब तक लिए गए साहसिक, अप्रत्याशित और दूरगामी परिणाम देने वाले निर्णयों की श्रृंखला का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय भी है।

नितिन नबीन बिहार की राजनीति में कोई नया नाम नहीं हैं। वे पांच बार विधायक रह चुके हैं और जमीनी राजनीति की बारीकियों से भलीभांति परिचित हैं। संगठन और सरकार- दोनों के अनुभव से संपन्न नितिन नबीन ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। इसके साथ ही संगठन के विभिन्न स्तरों पर उन्होंने जिस अनुशासन, रणनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है, वही उन्हें इस पद के लिए स्वाभाविक विकल्प बनाता है। उनका राजनीतिक व्यक्तित्व केवल भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि संगठन खड़ा करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और वैचारिक प्रतिबद्धता बनाए रखने की क्षमता से परिपूर्ण है। यही गुण भाजपा की आत्मा भी है-जहां व्यक्ति नहीं, संगठन सर्वोपरि होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का एक स्थायी गुण रहा है-नए चेहरों पर भरोसा और पीढ़ीगत नेतृत्व का निर्माण। चाहे वह केंद्र सरकार में मंत्रियों का चयन हो, राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हो या संगठन में बदलाव-मोदी ने बार-बार यह साबित किया है कि वे भविष्य की राजनीति को आज गढ़ने में विश्वास रखते हैं। नितिन नबीन का चयन भी इसी विचारधारा का प्रतिफल है। यह निर्णय संकेत देता है कि भाजपा अब केवल चुनाव जीतने की पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि अगले दो-तीन दशकों के लिए एक स्थायी वैचारिक और संगठनात्मक नेतृत्व तैयार कर रही है। युवा पीढ़ी, विशेषकर पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को आकर्षित करने की दृष्टि से यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद केवल संगठनात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक संतुलन का केंद्र भी होता है। इस पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति और समर्थन अनिवार्य माना जाता है। भाजपा की चुनावी सफलताओं में संघ की भूमिका सदैव निर्णायक रही है-चाहे वह विचार-प्रसार हो, कार्यकर्ता निर्माण हो या सामाजिक संपर्क। पिछले कुछ चुनावों में जिन परिस्थितियों का सामना पार्टी को करना पड़ा, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि भाजपा संगठन और संघ के बीच पूर्ण सामंजस्य कितना आवश्यक है। ऐसे में नितिन नबीन का चयन यह संकेत देता है कि संघ और पार्टी नेतृत्व के बीच गहन विमर्श और सहमति के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। यह नियुक्ति भाजपा को वैचारिक रूप से और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

नितिन नबीन के सामने सबसे बड़ी और तात्कालिक चुनौती पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव हैं। यह राज्य लंबे समय से भाजपा के लिए रणनीतिक और वैचारिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा है। यहां केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति, राष्ट्रवाद और सामाजिक संतुलन की भी परीक्षा होती है। एक संगठनात्मक अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की वास्तविक कसौटी यहीं होगी। यदि वे बंगाल में संगठन को नई धार देने, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और जनता के बीच विश्वास स्थापित करने में सफल होते हैं, तो उनका नेतृत्व स्वतः ही प्रमाणित हो जाएगा। यही वह मंच है, जहां उनका रुतबा, कौशल और रणनीतिक दृष्टि राष्ट्रीय राजनीति के सामने स्पष्ट होगी।

भाजपा की राजनीति में एक विशेष परंपरा रही है-जहां कयास कुछ और होते हैं और निर्णय बिल्कुल अलग दिशा से आता है। अनेक नाम चर्चा में रहते हैं, अनेक चेहरे मंजिल के निकट आकर भी ठहर जाते हैं, किंतु अंतिम निर्णय अक्सर सबको चौंकाने वाला होता है। यही भाजपा की 'चमत्कार करने वाली' संगठनात्मक शैली है। नितिन नबीन का मनोनयन भी इसी परंपरा का हिस्सा है। यह निर्णय उन तमाम अटकलों पर विराम लगाने की क्षमता रखता है, जो लंबे समय से अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के भीतर चल रही थीं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भाजपा में पद नहीं, क्षमता निर्णायक होती है।

नितिन नबीन भारतीय राजनीति की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने संगठनात्मक निष्ठा, वैचारिक स्पष्टता और सतत जनसंपर्क को अपनी राजनीतिक पहचान बनाया है। छात्र राजनीति से लेकर सक्रिय सार्वजनिक जीवन तक उनका सफ़र अनुशासन, कर्मठता, राष्ट्रीयता और संघर्ष की पाठशाला रहा है। वे जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने वाले, जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता से समझने वाले और उन्हें प्रशासनिक व राजनीतिक मंचों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने वाले नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। नितिन नबीन की कार्यशैली में युवाओं के प्रति विश्वास, विकासोन्मुख सोच और पारदर्शिता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे पद को नहीं, दायित्व को प्राथमिकता देते हैं और संगठन के मूल्यों के अनुरूप निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं।

नितिन नबीन सिन्हा कायस्थ समुदाय के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। अभी उन्हें जेपी नड्डा की जगह पर भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है जो अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यभार संभालेंगे। वे वर्तमान में बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री है। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में लगभग 84,000 वोटों से जीत हासिल की। पिछले चुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को भारी अंतर से हराया था। पुष्पम प्रिया चौधरी भी इस चुनाव में भारी अंतर से हार गईं। वे पटना जिले के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार विधान सभा के सदस्य हैं। 2 मार्च 2017 को, नबीन ने बिहार कांग्रेस के नेता अब्दुल जलील मस्तान के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया और उनकी नागरिकता पर सवाल उठाया। मस्तान ने कथित तौर पर एक रैली में भीड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को जूतों से मारने के लिए कहा था।

भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक सशक्त संगठनात्मक आंदोलन है, जिसकी आत्मा उसका अनुशासित, समर्पित और वैचारिक रूप से सजग कार्यकर्ता है। पार्टी का संगठनात्मक ढाँचा बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सहभागिता, संवाद और सामूहिक निर्णय की परंपरा को मजबूत करता है। संगठन नेतृत्व के प्रति कार्यकर्ताओं का अटूट विश्वास, स्पष्ट दिशा और नेतृत्व की पारदर्शिता भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ कार्यकर्ता स्वयं को सत्ता का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सहभागी मानता है। यही कारण है कि भाजपा में नेतृत्व और कार्यकर्ता के बीच विश्वास, प्रतिबद्धता और परस्पर सम्मान का संबंध दिखाई देता है, जो पार्टी को निरंतर सशक्त और गतिशील बनाए रखता है। नितिन नबीन का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनयन केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं, बल्कि भाजपा के भविष्य की राजनीति का स्पष्ट संकेत है। यह युवा नेतृत्व, वैचारिक प्रतिबद्धता, संगठनात्मक अनुशासन और संघ-समन्वय का संगम है। यदि नितिन नबीन इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाते हैं-विशेषकर पश्चिम बंगाल जैसी कठिन राजनीतिक भूमि पर-तो वे न केवल भाजपा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेंगे, बल्कि भारतीय राजनीति में युवा नेतृत्व की नई परिभाषा भी गढ़ेंगे। यही वह क्षण है, जहां राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि दृष्टि, धैर्य और दूरदर्शिता का प्रमाण बन जाती है।

अदालत पर राजनीतिक दखलंदाजी का सियासी प्रयोग है महाभियोग

मनोज कुमार अग्रवाल

मद्रास हाइकोर्ट के न्यायाधीश के एक फैसले को लेकर देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के 107 सांसदों ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन को पद से हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक महाभियोग प्रस्ताव सौंपा है । इस प्रस्ताव में कांग्रेस, डीएमके आप , सपा, सीपीआई, सीपीएम, और शिवसेना (उद्धव ठाकरे) सहित कई प्रमुख दलों के सांसदों के हस्ताक्षर हैं। नियम के अनुसार, किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है,इंडिया ब्लॉक के 107 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं।

आपको बता दें कि इस पूरे राजनीतिक विवाद की पृष्ठभूमि में न्यायमूर्ति स्वामीनाथन का एक फैसला है। पिछले हफ्ते, उन्होंने तमिलनाडु के तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित 6वीं शताब्दी के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के प्रशासन को एक निर्देश दिया। यह निर्देश था कि 13वीं शताब्दी की सिकंदर बादुशाह दरगाह के पास एक स्तंभ पर दीपक जलाने की परंपरा को फिर से शुरू किया जाए। जब राज्य सरकार ने विरोध किया और मंदिर प्रबंधन ने पालन नहीं किया, तो जज ने अवमानना का आदेश भी जारी किया।न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने अपने आदेशों का पालन न करने पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के लिए भी तलब किया है। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, मैं यहां हाथ उठाकर असहाय होकर यह कहने के लिए नहीं हूं कि, हे पिता, उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यह जानबूझकर उल्लंघन है। उन्होंने केओसुबल की रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया था कि मदुरै पुलिस आयुक्त ने 200 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ अदालत के आदेश का पालन करने से केओसुबल टुकड़ी को रोका था। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों के 56 पूर्व न्यायाधीशों ने विपक्षी सांसदों द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की पहल को लेकर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि यह कदम उन न्यायाधीशों को दबाव में लाने का प्रयास है जो राजनीतिक या वैचारिक उम्मीदों के अनुरूप फैसले नहीं देते। 12 दिसंबर को जारी संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बुनियाद को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा कि महाभियोग का इस्तेमाल न्यायिक आचरण की रक्षा के लिए होता है, न कि राजनीतिक हथियार की तरह।

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को हटाने की मांग करते हुए 100 से अधिक सांसदों की ओर से लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ बड़ा विरोध सामने आया. 50 से अधिक पूर्व न्यायाधीशों, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और कई हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, ने एक कड़े शब्दों वाला पत्र जारी कर इस कदम की कड़ी निंदा की. उन्होंने इस कदम को जजों को डराने-धमकाने की खुली कोशिश बताया.पूर्व जजों ने कहा कि कार्तिगई दीपम दीप-प्रज्वलन मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर जस्टिस स्वामीनाथन को हटाने की कोशिश लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ें हिला देने वाली है. उन्होंने लिखा कि सांसदों द्वारा बताए गए कारण सतही और इतने गंभीर संवैधानिक कदम के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं.

पत्र में पूर्व जजों ने इस कोशिश को न्यायपालिका को कमजोर करने वाली लंबी और चिंताजनक राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बताया. उन्होंने आपातकाल के बाद तीन वरिष्ठ जजों की सुपरसिडिंग, जस्टिस एचआर खन्ना की उपेक्षा और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़ और अब सीजेआई सूर्याकांत के खिलाफ चलाए गए राजनीतिक अभियान का उल्लेख किया।

पूर्व न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि महाभियोग जैसे संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल आर्म-ट्विस्टिंग और बदले की राजनीति के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, "आज निशाना एक जज है, कल पूरा संस्थान निशाने पर होगा."

पूर्व जजों ने सांसदों, बार काउंसिल, सिविल सोसाइटी और नागरिकों से अपील की कि इस कदम को शुरुआत में ही रोक दिया जाए, क्योंकि जज संविधान के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि राजनीतिक समूहों की पसंद-नापसंद के प्रति कोई जबाबदेही

बता दें कि यह पूरा विवाद तमिलनाडू में तब उठा, जब जस्टिस स्वामीनाथन ने तिरुप्परंकुंद्रम हिल पर दीपथून स्तंभ पर कार्तिगई दीपम का दीप जलाने का आदेश दिया. यह स्थान सिकंदर बादूशा दरगाह के पास है और लंबे समय से संवेदनशील माना जाता रहा है. याचिकाकर्ताओं की मांग पर जज ने 4 दिसंबर शाम 6 बजे तक दीप जलाने का निर्देश दिया. उन्होंने दलील दी कि यह कदम मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन दीप न जलाने से पहाड़ी पर मंदिर के अधिकार कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि वहां कथित अतिक्रमण की शिकायतें उठती रही हैं.

हालांकि तमिलनाडू सरकार ने यह कहते हुए कि इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है, आदेश लागू करने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच झड़पें भी हुईं. डीएमके ने आरोप लगाया कि जज ने 2017 की डिवीजन बेंच के आदेश को उलट दिया है और उनका निर्देश चुनाव से ठीक पहले सांप्रदायिक तनाव भड़का सकता है. पार्टी नेता टीआर बालू ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि बीजेपी राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है.

वहीं तमिलनाडू बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेन्द्रन ने महाभियोग प्रस्ताव को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया. उन्होंने कहा कि डीएमके न्यायिक फैसले तभी स्वीकार करती है जब वे उसके हित में हों. भाजपा नेता ने कहा कि जस्टिस स्वामीनाथन ने कोई अपराध नहीं किया और मंदिर व पुलिस प्रशासन की विफलता के कारण ही उन्हें आदेश देना पड़ा. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के महाभियोग प्रयास गलत परंपरा कायम करेंगे और संस्थानों के बीच टकराव को जन्म दे सकते हैं. आपको पता रहे यह मुद्दा सिर्फ अदालत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पिछले हफ्ते लोकसभा में भी बवाल मच गया था। डीएमके सदस्यों ने सदन में विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। वहीं, केंद्रीय उपमंत्री एल. मुरुगन ने डीएमके पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का पलटवार किया। डीएमके सांसद टीआर बालू ने सदन में न्यायमूर्ति स्वामीनाथन के एक विशेष विचारधारा के प्रति निष्ठा रखने की आलोचना की, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यायपालिका पर आक्षेप न लगाने की चेतावनी दी थी। अब स्पीकर ओम बिरला के सामने इन आरोपों की जांच और प्रस्ताव पर निर्णय लेने की बड़ी जिम्मेदारी है। देखना है कि इस मामले का पटाक्षेप किस तरह होता है।

खरपतवार-आजीविका के लिए खतरा

आज भी भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। देश की 48 फीसदी आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। देश की अर्थव्यवस्था में भी कृषि क्षेत्र की भागीदारी 16.61 प्रतिशत है। हालांकि कृषि जनित कच्चे माल पर कई प्रकार के उद्योग भी निर्भर हैं। खासकर कपड़ा उद्योग, खांड उद्योग, पटसन उद्योग, सारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि। कहा जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादन का भी एक भाग कृषि पर निर्भर करता है। कृषि भारत में पशुपालन से जुडी है। हर किसान पशुपालन से अतिरिक्त आय के अलावा गोबर की खाद की व्यवस्था करना चाहता है। परंपरा से पशुपालन खेती की जमीन के अलावा वन या चरागाह की जमीन पर निर्भर रहा है।

किन्तु पिछले कुछ दशकों से जब से हरित क्रांति के माध्यम से विदेशी बीजों के साथ विदेशी आक्रामक खरपतवार देश में आए हैं, तब से उनका वन और चरागाह की भूमि पर फैलाव भयानक रूप ले चुका है।

लैंटाना, यूपिटोरियम, पार्थेनियम गत दिनों डाउन टू अर्थ ने नेचर ससटेनेबिलिटी रिसर्च संस्थान की एक रपट प्रकाशित की है, जिसमें बहुत दिनों से चिंता का कारण बनी खरपतवार की समस्या पर वैज्ञानिक शोध की मुहर लगा दी है। इसके मुताबिक हर वर्ष भारत में 15,500 वर्ग किलोमीटर गैर कृषि क्षेत्र आक्रामक खरपतवारों की चपेट में आ रहा है, जिससे 14.40 करोड़ आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। इसके साथ कृषि भूमि और वन्यप्राणी आवास भी प्रभावित हो रहे हैं। 27.9 करोड़ पशु, और 2 लाख वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि के छोटे किसान प्रभावित हो रहे हैं। हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर और पश्चिमी घाट के क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। 2022 तक खरपतवारों के आक्रमण से 266,954 वर्ग किलोमीटर पशु चारा क्षेत्र और 212,450 वर्ग किलोमीटर शाकाहारी वन्यप्राणी आवास और 105,725 वर्ग किलोमीटर टाइगर आवास खरपतवारों के कारण अनुउत्पादक हो चुके हैं।

भारत का 2/3 प्राकृतिक क्षेत्र खरपतवारों की चपेट में आ चुका है, जिससे घुमंतू पशुपालक, घरेलू चरागाह आधारित पशुपालक और वन्यप्राणियों के लिए जरूरी घास चारा प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। इन संसाधनों पर निर्भर समुदाय आजीविका के संकट में आ गए हैं और कई बार विस्थापन के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक आकलन के अनुसार 1960 से 2020 तक 8 लाख,30 हजार करोड़ की हानि अर्थव्यवस्था को पंहुची है। जैव विविधता का जो विनाश खरपतवारों के कारण हुआ है, उसके कई प्रत्यक्ष नुकसान के अलावा अप्रत्यक्ष भी की हानि हुई है। वन्यप्राणी और मानव संघर्ष के बढ़ने से जनधन की हानि हो रही है। खासकर किसान ही इसका डंक झेल रहे हैं। हाथी, बंदर, सूअर,नीलगाय, और मांसाहारी शेर-चीता आदि भी वनों में भोजन न मिलने के कारण गांव या खेतों की ओर मुंह कर रहे हैं। एक ओर वन क्षेत्र घट रहा है, दूसरी ओर बचा हुआ अनुत्पादक होता जा रहा है।

हिमालय क्षेत्र पहले ही आजीविका कमाने की दृष्टि से संघर्ष पूर्ण क्षेत्र है, वहां स्थिति ज्यादा खराब है। यहां खेती और पशुपालन पर निर्भरता भी 90 प्रतिशत के आसपास है। वन्यप्राणी-मानव संघर्ष के चलते बहुत से क्षेत्रों में किसान अपनी जमीन खाली छोड़ने पर विवश हो चुके हैं। इसके अलावा ईंधन आपूर्ति और स्थानीय उपयोग के लिए विविध दस्तकारी के लिए कच्चा माल देने वाले उत्पाद और दवा-दूरी के लिए जड़ी-बूटी के न मिलने के कारण आजीविका के लिए स्थितियां कठिन तर होती जा रही हैं। हैरानी का विषय है कि आज तक इस समस्या को चिह्नत ही नहीं किया गया है। इसीलिए इसके समाधान के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था भी नहीं बन पाई है। यह अब प्रशासन और विज्ञान जगत के लिए एक चुनौती है कि वे किस कुशलता से इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेते हैं और इसके निराकरण के लिए मिशन मोड में प्रयास शुरू करते हैं। किसी प्राकृतिक संसाधन का इस तरह विनष्ट हो जाना राष्ट्रीय हानि है, जिसकी भरपाई समय पर न संभले तो करना कठिन हो जाएगी। हम हिमाचल प्रदेश में मनरेगा जैसे प्रावधानों को इस कार्य में प्रयोग करने का आग्रह सरकार से करते रहे हैं। आशा है इस दिशा में ध्यान दिया जाएगा और केंद्र सरकार को इस कार्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि राज्य सरकारों के पास खास कर हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड जैसे राज्य जो अपना खर्च कर्ज लेकर चलाने को मजबूर हैं उनके लिए एक नया बोझ संभालना आसान नहीं है।

पंजाब पुलिस ने मुंबई से दबोचे बीकेआई के दो आतंकी

चंडीगढ़, एजेंसी।

पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े गैंगस्टर से आतंकवादी बने दो व्यक्तियों को मुंबई से गिरफ्तार किया। सोमवार को पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान साजन मसीह निवासी वेरोके, गुरदासपुर और सुखदेव कुमार उर्फ मनीष बेदी निवासी लाहौरी गेट, अमृतसर के रूप में हुई है। दोनों बड़े अपराधिक पृष्ठभूमि वाले आरोपित हैं और उनके खिलाफ बटाला और अमृतसर के विभिन्न थानों में हत्या, इरादतन कत्ल, हथियारों एवं विस्फोटक पदार्थों से संबंधित और गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) एक्ट (यूएपीए) के तहत कई मामले दर्ज हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपित पाकिस्तान आधारित आईएसआई-समर्थित हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और अमेरिका आधारित बीकेआई-ऑपरेटिव हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया (हिरासत में) के अहम साथी थे। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपी दुबई और आर्मेनिया सहित विदेशी स्थानों से काम कर रहे थे और पंजाब में अपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधियां अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे।

बीज कंपनियां किसानों की कीमत पर कमा रही हैं मुनाफा: कोडंडा रेड्डी

हैदराबाद,एजेंसी।

तेलंगाना किसान आयोग के चेयरमैन कोडंडा रेड्डी ने सोमवार को कहा कि बीज राष्ट्रीय स्तर और तेलंगाना की खेती का अहम हिस्सा हैं, लेकिन इन बीजों की खेती करने वाले किसानों से ज्यादा मुनाफा बीज कंपनियां कमा रही हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि किसान आयोग ने केंद्रीय बीज अधिनियम-2025 के प्रारूप की बारीकी से जांच की है और उसमें कई कमियां पाई हैं। किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग ने गोलमेज बैठकें कीं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज की आपूर्ति निर्बाध तरीके से हो सके। रेड्डी ने बताया कि विदेशी बीज कंपनियां 1994 से देश और राज्य में काम कर रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2004 में सरकार ने साफ कहा था कि मिलावटी बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा सरकार भी यही तरीका अपना रही है। कुछ कंपनियां हालांकि जाने-माने ब्रांड नामों के तहत नकली बीज बेच रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अकेले तेलंगाना में देश की लगभग 40 प्रतिशत बीज की खेती होती है, जो लाखों एकड़ में फैली हुई है।

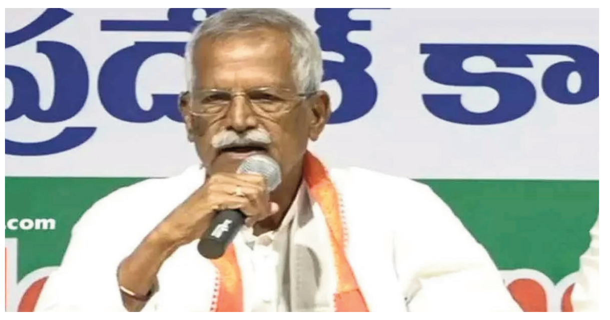

उन्होंने मुलुगु जिले का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां मक्के के बीज की खेती करने वाले आदिवासी किसानों को कुछ बीज कंपनियों की मनमानी के कारण भारी नुकसान हुआ। इसके बाद आयोग ने दखल दिया, एक विशेष समिति बनाई और एक विस्तृत रिपोर्ट हासिल की। उन्होंने बताया, मुलुगु में बीज की खेती करने वाले किसान बीमार पड़ गए और खराब बीजों के असर से मवेशी भी मर गए। कई बैठकों के बाद, हम प्रभावित आदिवासी किसानों को इंसाफ दिला पाए। आयोग ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से चार करोड़ रुपये तक का मुआवजा दिलवाया, जिसे उन्होंने देश के इतिहास में अपनी तरह का पहला मामला बताया।

रेड्डी ने कहा कि आयोग ने सिफारिश की है कि प्रस्तावित बीज अधिनियम में मुआवजा व्यवस्था भी शामिल की जाए, क्योंकि नकली बीजों के कारण फसल खराब होने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और वे लागत भी वसूल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1966 में ही दूरदर्शिता के साथ एक कानून बनाया गया था, लेकिन हाल के सालों में नकली बीजों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। आयोग ने इन मुद्दों को हल करने के लिए सबूत पेश किए हैं और केंद्रीय बीज अधिनियम के प्रारूप में संशोधन के सुझाव दिए हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि खेती राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए राज्यों को भी कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। यह सवाल उठाते हुए कि क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कहीं और से मंजूरी लेकर राज्यों में बीज बेचने की इजाजत दी जानी चाहिए, उन्होंने तर्क दिया कि बीज की बिक्री को विनियमित करने में राज्य सरकारों के पास ज्यादा अधिकार होने चाहिए।

उन्होंने ऐसे मामलों का भी जिक्र किया, जिसमें पार्थेनियम (गाजर घास) जैसे नुकसान पहुंचाने वाले पौधे गेहूं की फसलों में उग आए और प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा (कीकर) दूषित बीजों से फैल गया, जिससे पूरे राज्य में खेती पर असर पड़ा।

उन्होंने आगे कहा कि इन सभी मुद्दों को केंद्र सरकार के ध्यान में लाया गया है।श्री रेड्डी ने हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की राज्य सरकार ने मिलावटी बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए संशोधन लाने की कोशिश की थी, मगर भाजपा सरकार होने के बावजूद विधेयक राज्यपाल के पास लंबित है। कमीशन को इस बारे में अध्ययन के लिए किये गये हरियाणा दौरे पर यह जानकारी मिली।

पति-पत्नी के बीच लंबा अलगाव दोनों के लिए क्रूरता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अलग-अलग रह रहे पति-पत्नी की तलाक अर्जी को मंजूरी देते हुए कहा कि सुलह की कोई उम्मीद न होने के चलते दंपति का लंबे समय तक एक-दूसरे से अलग रहना दोनों पक्षों के प्रति क्रूरता के समान है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि चार अगस्त 2000 को शादी के बंधन में बंधने वाले दंपति ने विवाह के महज दो साल बाद 2003 में मुकदमेबाजी शुरू कर दी और विचारों में मतभेद के कारण 24 वर्षों से अलग रह रहे हैं।

पीठ ने कहा कि अदालतों की ओर से बार-बार प्रयास किए जाने के बावजूद दोनों पक्षों के बीच कोई सुलह-समझौता नहीं हुआ।

पीठ ने कहा कि कई मामलों में इस अदालत के सामने ऐसी स्थितियां आई हैं, जहां पक्षकार काफी समय से अलग रह रहे हैं और यह लगातार माना गया है कि सुलह की कोई उम्मीद के बिना लंबे समय तक अलग रहना दोनों पक्षों के लिए क्रूरता के बराबर है। शीर्ष अदालत ने कहा, ''यह न्यायालय भी इस बात से सहमत है कि वैवाहिक विवाद से जुड़े मुकदमों का लंबे समय तक लंबित रहना विवाह को केवल कागजों तक सीमित कर देता है। ऐसे मामलों में जहां मुकदमा काफी समय से लंबित है, पक्षों के बीच संबंध तोड़ देना ही पक्षों और समाज के हित में है।

पीठ ने कहा, इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि पक्षों को राहत दिए बिना वैवाहिक मुकदमे को अदालत में लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शिलांग निवासी दंपति के विवाह को भंग करने का आदेश दिया। उसने शिलांग के अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक) के आदेश को बरकरार रखा और उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने पत्नी की इस दलील पर विवाह को बहाल किया था कि उसका पति को स्थायी रूप से त्यागने या छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।

पीठ ने कहा कि इस मामले में पति-पत्नी वैवाहिक जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को लेकर दृढ़ मत रखते हैं और उन्होंने लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ तालमेल बैठाने से इनकार कर दिया था।

भाजपा ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद का शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह में सोमवार को संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है।

भाजपा ने अपने सभी सांसदों से उन्हें 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि इस दौरान कई अहम विधेयक सदन में पेश किये जाएंगे।

शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलना है। सरकार आगामी दिनों में नया परमाणु ऊर्जा (शांति) विधेयक पेश कर सकती है। वहीं सत्र के दौरान कॉर्पोरेट विधेयक और उच्च शिक्षा संबंधी विधेयक पर भी चर्चा होने की संभावना है।

दयानिधि मारन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली, एजेंसी।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद दयानिधि मारन के चेन्नई सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से 2024 के लोकसभा चुनावों में चुने जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने एमएल रवि द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। रवि ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनकी चुनाव याचिका खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि श्री मारन ने मतदान से पहले 48 घंटे की ₹मौन अवधि₹ के दौरान अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करके और पर्चे बांटकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भ्रष्ट चुनावी गतिविधियों में लिप्त हुए थे।

यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने अपर्याप्त दलीलों के आधार पर भ्रष्ट आचरण के विचारणीय मुद्दे को खारिज करने में स्पष्ट त्रुटि की है और यह कि मौन अवधि के दौरान किए गए विज्ञापन एक विचारणीय मुद्दा हैं जिन पर पूर्ण सुनवाई की आवश्यकता है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील से चुनाव में याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बारे में पूछा।

सार समाचार

शिवसेना (यूबीटी) नेता तेजस्वी घोसालकर भाजपा में हुई शामिल

मुंबई,एजेंसी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की नेता तेजस्वी घोसालकर ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। सुश्री तेजस्वी घोसालकर दिवंगत पार्टी नेता अभिषेक घोसालकर की पत्नी है जिनकी पिछले साल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटनाक्रम बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले सामने आया है। उन्हें मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सतम ने पार्टी में शामिल किया। यह घटनाक्रम चुनाव से पहले शिवसेना (यूबीटी) के लिए विशेष रूप से शहर के पश्चिमी उपनगरों में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सुश्री तेजस्वी ने अपना त्यागपत्र सौंपने के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक कार्य, सार्वजनिक सेवा और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में बहुत कठिनाई हो रही थी।

राजनाथ सिंह आज रक्षा संपदा दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे

नई दिल्ली,एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को यहां रक्षा संपदा भवन में रक्षा संपदा दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और 61 छावनी बोर्डों के रक्षा भूमि प्रबंधन तथा नगर प्रशासन के क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टत कार्य के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि इस वर्ष के समारोह का विशेष महत्व है क्योंकि विभाग अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह 1765 की विरासत को मना रहा है जब पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पहला छावनी बोर्ड स्थापित किया गया था।

इसके बाद दानापुर (1766), मेरठ (1803), अंबाला (1843) और दिल्ली (1915) जैसे छावनी बोर्ड बने जिन्होंने भारत में रक्षा और भूमि प्रशासन की नींव रखी। बाद में 16 दिसंबर, 1926 को रक्षा मंत्रालय के तहत भूमि और छावनी बोर्ड विभाग के रूप में इसे औपचारिक रूप दिया गया। रक्षा संपदा विभाग, रक्षा मंत्रालय के तहत सरकार की सबसे बड़ी भूमि संपत्ति का प्रबंधन करता है।

इस विभाग ने एक असाधारण आधुनिकीकरण यात्रा शुरू की है और खुद को डिजिटल और तकनीक-सक्षम भूमि प्रबंधन में एक अग्रणी के रूप में बदल दिया है।

पंजाब के स्कूलों को मिल रही धमकियों की हो एनआईए जांच : चुग

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पंजाब में स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच फैले भय और दहशत के माहौल पर कड़ी आपत्ति जताई। चुग ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की नालायकी के कारण आज यह स्थिति पंजाब में हुई है। सोमवार को मीडिया से बातचीत में चुग ने एनआईए से जांच की मांग करते हुए कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि पंजाब के बच्चों और उनके माता-पिता को डराने के लिए रची गई एक सोची-समझी साज़िश प्रतीत होती है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है।

चुग ने सवाल उठाया कि क्या भगवंत मान सरकार अनजाने में आईएसआई जैसी ताक़तों के इशारों पर खेल रही है या फिर वह पंजाब में सक्रिय अराजक तत्वों पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। चुग ने कहा कि पंजाब का बच्चा-बच्चा जानता है कि गैंगस्टर और माफिया बेख़ौफ होकर खुलेआम घूम रहे हैं। आए दिन गोलियां चलना और व्यापारियों व आम लोगों को धमकी भरे फिरौती कॉल आना अब सामान्य बात बन चुकी है।

राष्ट्रपति 16 से 22 दिसंबर तक कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के दौरे पर

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 16 से 22 दिसंबर तक कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति दौरे के पहले दिन 16 दिसंबर को कर्नाटक के मांड्या जिले के मलवल्ली में आदि जगद्गुरु श्री शिवरात्रेश्वर शिवयोगी महास्वामीजी की 1066वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति 17 दिसंबर को तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित स्वर्ण मंदिर में दर्शन एवं आरती करेंगी। इसके बाद वह शीतकालीन प्रवास के लिए सिकंदराबाद के बोलारम स्थित राष्ट्रपति निलयम पहुंचेंगी। राष्ट्रपति 19 दिसंबर को हैदराबाद में तेलंगाना लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी।

वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार का बयान वैज्ञानिक तथ्यों से उलट : जयराम रमेश

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राज्यसभा में वायु प्रदूषण और उससे होने वाली मौतों और बीमारियों को लेकर केंद्र सरकार के बयान पर एक पत्र जारी कर चौंकाने वाला और असंवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण सरकार के दावे का पूरी तरह खंडन करते हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली में सोमवार को कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 500 या उससे अधिक दर्ज किया गया।

जयराम रमेश ने कहा कि 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में यह दावा किया कि देश में ऐसा कोई पक्का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि मृत्यु

या बीमारी का सीधा संबंध केवल वायु प्रदूषण से है। उन्होंने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि इससे पहले 29 जुलाई 2024 को भी सरकार ने इसी तरह का बयान दिया था। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययन सरकार के दावे के विपरीत हैं। उन्होंने जुलाई 2024 में द लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि भारत में कुल मौतों का 7.2 प्रतिशत वायु प्रदूषण से जुड़ा है और केवल 10 शहरों में ही हर साल लगभग 34 हजार मौतें इससे संबंधित हैं।

उन्होंने मुंबई स्थित इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज़ के अध्ययन का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन जिलों में वायु प्रदूषण नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स से अधिक है, वहां वयस्कों में समय से पहले मृत्यु का खतरा 13 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, जबकि बच्चों में मृत्यु दर में लगभग दोगुनी वृद्धि देखी गई है।

जयराम रमेश ने द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि भारत में हर साल 15 से 20 लाख मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी होती हैं और यह समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है।

प्रधान ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पेश किया

नई दिल्ली, एजेंसी।

लोकसभा में सोमवार को उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए सरल नियामक प्रणालियों तैयार करने वाले विधेयक को पेश किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025' पेश किया। विधेयक के अंतर्गत तीन परिषदों के साथ एक विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना की जाएगी। सरकार ने इस विधेयक एक संयुक्त समिति को भेजने की मंशा जाहिर की है। शिक्षा मंत्री प्रधान ने बिल पेश करते हुए कहा कि यह कानून उच्च शिक्षा संस्थानों में मानक तय करने, रेगुलेशन को कोऑर्डिनेट करने और बेहतरीन काम, स्वायत्ता और पारदर्शी मान्यता को बढ़ावा देने के लिए 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान'

स्थापित करना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह कानून विश्वविद्यालयों और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र सेल्फ-गवर्निंग संस्थान बनने में मदद करना चाहता है।

बाद में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को सौंपने का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने कहा कि कई सांसदों ने आग्रह किया है कि यह एक बड़ा बिल है और उन्हें इस बिल पर और चर्चा करने की ज़रूरत है। इसलिए, सरकार इस बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव देती है। विधेयक में 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' की स्थापना का उबंद है। इसके अलावा तीन परिषदों का भी गठन किया जाएगा, जिनमें विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद, विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद तथा विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद शामिल हैं। इनका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षण, अध्ययन, शोध और नवाचार में उत्कृष्ट बनाना तथा शिक्षा के मानकों में बेहतर तालमेल और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 को समाप्त करने का भी प्रस्ताव करता है। 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' एक शीर्ष संस्था होगी, जो उच्च शिक्षा के समग्र विकास के लिए दिशा-निर्देश देगी और सभी परिषदों के बीच समन्वय बनाए रखेगी।

पंजाब में राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब के मोहाली में गैंगस्टरों ने कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी एवं स्पोर्ट्स प्रमोटर की गोली मारकर हत्या कर दी।

घटना सोमवार की शाम मोहाली के गांव सोहना में उसे समय हुई, जब यहां कबड्डी के मैच चल रहे थे। हमले की जिम्मेदारी बंबीहा गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ली है।

मृतक कबड्डी खिलाड़ी राणा बलचौरिया की 10 दिन पहले ही शादी हुई थी। मोहाली के सेक्टर 82 स्थित एक खेल के मैदान में वैदवान स्पोर्ट्स क्लब सोहाना की तरफ से कबड्डी मैच करवाया जा रहा था।

धानमंत्री पर राहुल गांधी की टिप्पणी अमर्यादित : आठवले

नई दिल्ली, एजेंसी।

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी से संसद के पटल पर और देश से माफी मांगने की मांग की।

सोमवार को आऱपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की गई टिप्पणी अमर्यादित और अस्वीकार्य है और सार्वजनिक मंच से दिये ऐसे बयान से कांग्रेस का असली चरित्र सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के असंयमित बयान और

कांग्रेस की हरकतें उनकी हताशा को दर्शाती हैं, क्योंकि वे चुनावों में लगातार मिलती हार के बाद अब संवैधानिक संस्थाओं को भी निशाना बना रहे हैं। रामदास आठवले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बाबासाहेब आंबेडकर रचित संविधान को धर्मग्रंथ सरीखा सम्मान देते हैं और प्रधानमंत्री हमेशा पार्टी नेताओं को विपक्ष को दुश्मन नहीं, बल्कि राजनीतिक विरोधी मानने की सलाह देते हैं।

डीजीसीए की जांच समिति ने इंडिगो के मुख्यालय का किया दौरा

नई दिल्ली, एजेंसी।

इंडिगो एयरलाइंस में हालिया परिचालन संबंधी व्यवधानों की जांच कर रही विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की विशेष समिति ने एयरलाइन के गुरुग्राम स्थित मुख्यालय का दौरा किया है।

आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को दी जानकारी में बताया कि नियामक की ओर से गठित यह विशेष समिति एयरलाइन के सिस्टम में आई खामियों और फ्लाइट्स के प्रबंधन में हुई लापरवाही की गहन पड़ताल कर रही है। इंडिगो मुख्यालय का यह दौरा इस जांच प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा माना जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन परिचालन मानकों का कड़ाई से पालन कर रही है या नहीं।

घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो में बड़े पैमाने पर परिचालन व्यवधानों की जांच के लिए नागर विमानन महानिदेशक फैज अहमद किदवई ने इस महीने की शुरुआत में इस 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था। डीजीसीए की चार सदस्यीय समिति ने एयरलाइन के मुख्यालय का दौरा किया।

इस दौरान इस समिति के सदस्यों ने उन कई पहलुओं की जांच की है, जो परिचालन में व्यवधान का कारण बन सकते थे।

सहमति के बिना लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता और प्रतिनिधित्व के बिना वैधता नहीं हो सकती

राज्य सभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान आरोप-प्रत्यारोप

नई दिल्ली, एजेंसी।

राज्य सभा में सोमवार दोपहर एक बजे से चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान पक्ष औऱ विपक्ष की तरफ से जम कर आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए। चुनाव सुधारों पर चर्चा को जारी रखते हुए एआईएडीएमके सांसद डॉ. एम. थंबीदुरै ने कहा कि उनकी पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे हर कदम पर भरोसा है। स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत करती है, पारदर्शिता मतदाताओं को सशक्त बनाती है और चुनाव प्रचार चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उन्होंने आगे कहा कि करूर की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राजनीतिक दलों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने का निर्देश दिया था, जिसे मद्रास हाई कोर्ट ने भी दोहराया, लेकिन अब तक सरकार ने कोई एसओपी तैयार नहीं की है।

इस पर सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने उनसे राज्य के मुद्दे न उठाने को कहा। इस पर थंबीदुरै ने कहा कि वे चुनाव से जुड़े मुद्दों पर ही बोल रहे हैं। चुनाव प्रचार भी चुनाव सुधारों का हिस्सा है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद गुरविंदर सिंह ओबेरॉय ने चुनाव सुधार की चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सहमति के बिना लोकतंत्र

अस्तित्व में नहीं रह सकता और प्रतिनिधित्व के बिना वैधता नहीं हो सकती। हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है, हम अनुच्छेद 370 को जिस तरीके से हटाया गया, उसे स्वीकार नहीं करते और हम इसे लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से चुनौती देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सत्ता से सच कहना चाहिए। चुप्पी को सहमति न समझा जाए, देरी को मंजूरी न माना जाए और आंदोलन की अनुपस्थिति को समर्थन न समझा जाए।

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब अब तक अमित शाह ने नहीं दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि या तो चुनाव आयोग केंद्रीय गृह मंत्री को गुमराह कर रहा है या केंद्रीय गृह मंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं।

दिग्विजय सिंह के इस बयान पर राज्य सभा में सत्ता पक्ष की ओर से शोर-शराबा हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप कुमार पाठक ने कहा कि आज राजनीति में कोई समान अवसर (लेवल प्लेइंग फील्ड) नहीं बचा है। उन्होंने राजनीतिक दलों की फंडिंग में सुधार की मांग की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चर्चा में सरकार से सवाल किया कि अगर जनता भाजपा के साथ है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या समस्या है? सरकार को बैलेट चुनाव से डरना नहीं चाहिए।

सार समाचार

रेत माफिया ने एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मारकर किया क्षतिग्रस्त

भिण्ड,एजेंसी। मध्यप्रदेश में भिण्ड जिले के लहार अनुभाग में रेत माफिया के हौसले बुलंद नजर आए। मिहोना बायपास पर आज अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे लहार के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) विजय सिंह यादव की गाड़ी को रेत माफिया के ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे वाहन आगे से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार एसडीएम विजय सिंह यादव को सुबह अवैध रेत परिवहन की सूचना मिली थी। वे मिहोना बायपास पहुंचे, जहां बिना रॉयल्टी और ओवरलोड रेत से भरी दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मिलीं। जब एसडीएम ने कार्रवाई के लिए वाहनों को रोकने का प्रयास किया, तो एक चालक ने जानबूझकर अपने ट्रैक्टर से एसडीएम की गाड़ी में टक्कर मार दी, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके।

बैतूल में 10 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी का पर्दाफाश

बैतूल,एजेंसी। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में अब तक के सबसे बड़े संगठित साइबर ठगी और अवैध ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बैतूल पुलिस ने महज सात माह में एक ही म्यूल बैंक खाते से 10 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन का खुलासा किया है। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि करोड़ों रुपये की मनी ट्रेल की जांच अभी जारी है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी के निर्देशन में गठित साइबर सेल और विशेष एसआईटी टीम ने इस संगठित नेटवर्क की परतें खोली हैं। जांच में सामने आया कि अवैध ऑनलाइन बेटिंग और साइबर ठगी से प्राप्त रकम पहले फर्जी फर्मों के करंट खातों में जमा की जाती थी और फिर म्यूल खातों के जरिए आगे ट्रांसफर की जाती थी।

नक्सल-मुक्त मध्य प्रदेश में अब विकास को मिलेगी नई रफ्तार : मोहन यादव

भोपाल, एजेंसी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश ने लगभग 35 साल नक्सलवाद का दंश झेला। यह एक बड़ी चुनौती थी, पर राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और नक्सल विरोधी अभियान में शामिल जवानों की प्रतिबद्धता से 11 दिसंबर 2025 को नक्सलवाद प्रदेश के नक्शे से पूरी तरह मिटा दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह दिन प्रदेश में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की धरती से नक्सलवाद को समूल खत्म करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नक्सलवाद और लाल आतंक देश के हर हिस्से में विकास आधारित गतिविधियों में बाधक था। इससे आम नागरिकों में इसके कारण भय का माहौल होता था। ऐसे में नक्सलियों और नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों ने बालाघाट में अंतिम दो नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराया और मध्य प्रदेश ने लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया। अब इससे प्रभावित क्षेत्रों में विकास को एक नई दिशा और एक नई रफ्तार मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि राज्य में विकास को गति देने के लिए मध्य प्रदेश में दशकों से चली आ रही नक्सलवाद की समस्या से खत्म करना अति आवश्यक था। मध्य प्रदेश ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह द्वारा देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय डेडलाइन से करीब साढ़े तीन महीने पहले ही यह ऐतिहासिल उपलब्धि हासिल कर ली है। नक्सलवादियों के एमएमसी जोन (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) में 42 दिन में 42 नक्सलवादियों ने समर्पण कर विकास की धारा से जुड़ना स्वीकार किया है। वहीं, प्रदेश में वर्ष 2025 में 10 हार्डकोर माओवादियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। उन्होंने इस सफलता का श्रेय राज्य के बहादुर पुलिस अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षाबलों को दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विशेष योजना बनाई है। साथ ही प्रदेश में अब एक ऐसा तंत्र भी विकसित किया जाएगा, जिससे दोबारा मध्यप्रदेश की धरती पर नक्सलवादी या अन्य अतिवादी मूवमेंट खड़े न हो पाएं। इसके लिए सभी पड़ोसी राज्यों के साथ भी जरूरी समन्वय किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 1988-90 से नक्सली गतिविधियों की शुरुआत हुई थी। नक्सलियों ने आम नागरिकों को डरा-धमकाकर परेशान किया और सरकार के विकास कार्यों में भी रुकावटें डालीं। नक्सली पुलिस की बसों को भी आग के हवाले कर देते थे। नक्सलियों ने विपक्षी दल की सरकार में मंत्री रहे लिखीराम कावरे की बालाघाट जिले में उनके घर से निकालकर सरेआम हत्या कर दी थी। प्रदेश में 35 सालों के लंबे समय तक नक्सलियों से संघर्ष जारी रहा, जिसमें कई आम नागरिक और पुलिस व सुरक्षाबलों के जवानों को अपने प्राण गंवाने पड़े।

मध्य प्रदेश में वर्ष 1988 से 1990 के बीच नक्सल गतिविधियों की शुरुआत हुई थी। प्रदेश में मंडला, डिंडौरी और बालाघाट नक्सल प्रभावित जिले रहे। राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला और डिंडौरी के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के 850 पद स्वीकृत किए। नक्सलियों को हथियार डालकर जीवन से जुड़ने का अवसर देने के लिए राज्य सरकार ने 'पुनर्वास से पुनर्जीवन' अभियान प्रारंभ किया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान खरीदी में अव्यवस्था पर विपक्ष का आक्रोश

रायपुर,एजेंसी।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को धान खरीदी व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न मिलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मौजूदा हालात यह संकेत देते हैं कि सरकार की प्राथमिकता धान खरीदी नहीं है।

उन्होंने आशंका जताई कि पूरी व्यवस्था को कमजोर कर इसे निजी हाथों में सौंपने की साजिश रची जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर विस्तृत चर्चा कराई जाती, तो सत्तापक्ष के विधायकों को भी अपनी बात रखने और सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलता।

उन्होंने आरोप लगाया कि धान खरीदी से जुड़े समितियों के प्रबंधक, कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर विचार करने के बजाय दमनात्मक कार्रवाई कर ही है।

भूपेश बघेल ने पंजीयन प्रक्रिया में खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि वन अधिकार पट्टा धारक किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया। ऑनलाइन टोकन प्रणाली भी बाधित है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई किसान एंड्रॉयड मोबाइल न होने के कारण चॉइस सेंटरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

उन्होंने महासमुंद जिले की एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यवस्था से हताश एक किसान ने आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशीलता नजर नहीं आई। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खरीदे गए धान का समय पर उठाव नहीं हो रहा है, जिससे केंद्रों पर संकट की स्थिति बनी हुई है।

पिछले सीजन का धान अब तक पूरी तरह नहीं उठ पाया, जो सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। अंत में उन्होंने आसंदी से मांग की कि धान खरीदी से जुड़े इस गंभीर मुद्दे को स्वीकार कर सदन में व्यापक चर्चा कराई जाए, ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान निकल सके।

संजय सरावगी बने बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष

पटना, एजेंसी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए दरभंगा शहरी क्षेत्र से छह बार के विधायक एवं पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी को बिहार प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह दरभंगा सदर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक हैं।

संजय सरावगी अब निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल का स्थान लेंगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की औपचारिक घोषणा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र के माध्यम से की गई है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

संजय सरावगी ने वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के उम्मीदवार उमेश साहनी को 24,593 मतों से पराजित किया था। उनका राजनीतिक सफर फरवरी 2005 में शुरू हुआ, जब उन्होंने दरभंगा सीट से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार मोहम्मद मुमताज को 14,188 मतों से हराकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया। इसके बाद अक्टूबर 2005 में उन्होंने कांग्रेस के डॉ. मदन मोहन झा को 24,983 मतों से पराजित कर दोबारा जीत दर्ज की।

संजय सरावगी ने वर्ष 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में भी लगातार जीत हासिल की। वर्ष 2010 में उन्होंने राजद के सुल्तान अहमद को 27,554 मतों से हराया, जबकि 2015 और 2020 में क्रमशः राजद उम्मीदवारों ओम प्रकाश खेरिया और अमर नाथ गामी को पराजित किया। वे नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

अपनी साफ-सुथरी छवि, प्रशासनिक अनुभव और मजबूत संगठनात्मक क्षमता के कारण पार्टी नेतृत्व ने उन्हें बिहार भाजपा की कमान सौंपी है। संजय सरावगी दरभंगा सदर सीट से लगातार छह बार विधायक चुने जा चुके हैं।

नीतीश कुमार ने नवनियुक्त चिकित्सक के चेहरे से हटाया हिजाब

पटना, एजेंसी।

बिहार में नवनियुक्त एक आयुष चिकित्सक उस समय असहज हो गई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र प्रदान करने के दौरान उसके चेहरे से हिजाब हटा दिया।

इस घटना का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है। यह घटना मुख्यमंत्री सचिवालय 'संवाद' में आयोजित उस कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां एक हजार से अधिक आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, नियुक्त किए गए डॉक्टरों में 685 आयुर्वेद, 393 होम्योपैथी और 205 यूनानी पद्धति के चिकित्सक शामिल हैं। इनमें से 10 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं मंच से नियुक्ति पत्र सौंपे, जबकि शेष को ऑनलाइन माध्यम से पत्र दिए गए। जब नुसरत परवीन की बारी आई, जो चेहरे पर हिजाब डाले हुई थीं, तो 75 वर्षीय मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा, "यह क्या है?" इसके बाद मुख्यमंत्री उनके चेहरे से हिजाब हटा दिया। घबराई हुई नवनियुक्त चिकित्सक को इसके बाद वहां मौजूद एक अधिकारी ने तुरंत एक ओर कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के बगल में खड़े उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें रोकने के प्रयास में उनकी आस्तीन खींचते हुए नजर आए। इधर, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया खातों पर साझा करते हुए दावा किया कि यह घटना जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख की अस्थिर मानसिक स्थिति" का ताजा उदाहरण है। राजद ने 'एक्स' पर लिखा, यह क्या हो गया है नीतीश जी को?

दतिया में कांग्रेस नेता ने की आत्महत्या

दतिया,एजेंसी। मध्यप्रदेश के दतिया जिले के भांडेर कस्बे में आज कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद जाहिद उद्दीन सिद्दीकी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक (80) पेशे से नोटरी वकील भी थे। घटना आज तड़के की बताई जा रही है। सुबह लगभग 8 बजे जब उनकी पत्नी कमरे में पहुंचीं, तो उन्होंने जाहिद उद्दीन को फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन में कोहराम मच गया और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना पर भांडेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसे जब्त कर लिया गया है।

जम्मू-कश्मीर की जलविद्युत परियोजनाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं: उमर

श्रीनगर, एजेंसी।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि यहां की जलविद्युत परियोजनाओं का राष्ट्रीय महत्व है और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। अब्दुल्ला ने यहां पत्रकारों से कहा कि इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि जो संस्थाएं पहले निर्वाचित सरकार के अधीन काम करती थीं उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का उल्लेख करते हुए श्री अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पास विद्युत मंत्रालय का प्रभार भी है लेकिन जम्मू-कश्मीर विद्युत विकास निगम को अभी तक निर्वाचित सरकार को वापस नहीं सौंपा गया है।

उन्होंने कहा, आप और मैं दोनों जानते हैं कि अगर यह आरोप मेरे किसी भी मंत्री के खिलाफ लगाया गया होता, तो भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो छापेमारी करती। जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में 850 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजना के निर्माण से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्थानीय भाजपा विधायक पर काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि लगातार व्यवधान के कारण कंपनी को परियोजना से पीछे हटना पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है और इस परियोजना की नींव 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रखी थी। चिनाब नदी पर बन रही 3,700 करोड़ रुपये की यह परियोजना केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू-कश्मीर नगर निगम परिषद (जेकेपीडीसी) का संयुक्त उद्यम है। उनोंने जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर में जलविद्युत परियोजनाएं केवल केंद्र शासित प्रदेश के लिए नहीं हैं बल्कि पूरे देश के लिए हैं।

नैनीताल के डीएम ने विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की

नैनीताल,एजेंसी। नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल स्थित विकास भवन में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सोमवार को राज्य, केंद्र एवं बाह्य सहायतित योजनाओं तथा 20 सूत्री कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की विभागवार वित्तीय व भौतिक प्रगति की गहन समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने जिन विभागों की प्रगति धीमी पाई गई और जहां लक्ष्य के सापेक्ष कम धनराशि व्यय हुई, उन विभागीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेते हुए 15 दिन में प्रगति में सुधार का निर्देश दिया। जिला योजना अंतर्गत उद्योग विभाग, लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई, समाज कल्याण एवं चिकित्सा विभाग द्वारा कम व्यय पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और अगले सप्ताह तक प्रगति सुनिश्चित करने को कहा।

पंजाब निकाय चुनाव में विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ेगा: पन्नू

चंडीगढ़, एजेंसी।

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के जनरल सेक्रेटरी बलतेज पन्नू ने सोमवार को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं क्योंकि उन्हें साफ तौर पर बड़ी हार दिख रही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पन्नू ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुए, जो पंजाब में कई दशकों में पहली बार हुआ है।

उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लोगों ने उत्साह से हिस्सा लिया और बिना किसी डर या दबाव के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया। पन्नू ने कहा कि कई सालों बाद, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में लोग वोट देने के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखे। यह खुद साबित करता है कि माहौल स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर था। मतदाता अब इन जमीनी संस्थानों के महत्व को समझ गए हैं। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पन्नू ने कहा कि बूथ कैप्चरिंग, धांधली और डराने-धमकाने के उनके दावे बेबुनियाद और मनगढ़ंत थे।

उन्होंने कहा कि पहले, इन्हीं पार्टियों ने आरोप लगाया था कि उम्मीदवारों को नॉमिनेशन पेपर दाखिल नहीं करने दिया गया। अब, जब फाइनल लिस्ट आ गई है, तो यह साफ दिखाता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इससे विपक्ष का झूठ बेनकाब हो गया है।

उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष जानता है कि वे बुरी तरह हार रहे हैं। इसीलिए वे 17 दिसंबर को नतीजे आने से पहले अफवाहें फैलाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में लोकल बॉडी चुनावों के इतिहास का जिक्र करते हुए पन्नू ने याद दिलाया कि 2008 और 2013 के चुनावों में एसएडी-भाजपा गठबंधन के दौरान और फिर 2018 में कांग्रेस सरकार के समय बड़े पैमाने पर हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और हत्याएं हुई थीं। पन्नू ने कहा कि इस बार पंजाब में कहीं भी बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, या जान-माल के नुकसान की एक भी शिकायत नहीं मिली है। कुछ बूथों पर दोबारा वोटिंग की खबरों पर सफाई देते हुए पन्नू ने कहा कि तकनीकी कारणों से सिर्फ 16 बूथों पर चुनाव रद्द किए गए थे, जैसे कि चुनाव चिह्नों या उम्मीदवारों के नामों की गलत छपाई, हिंसा की वजह से नहीं।

उन्होंने आगे कहा कि 17 दिसंबर को जब सही आंकड़े आएंगे, तो सब देखेंगे कि परसेंटेज के हिसाब से विपक्ष को कितने वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को उसकी गवर्नेंस और परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने कितने भारी बहुमत से वोट दिया है। विपक्ष की घबराहट साफ तौर पर लोगों के फैसले को दिखाती है।

बंगाल की खाड़ी में पांच भारतीय मछुआरे लापता

कोलकाता, एजेंसी। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में बंगाल की खाड़ी में पांच भारतीय मछुआरों की तलाश के लिए एक बड़ा तलाश अभियान शुरू किया है, जो एक बंगलादेशी जहाज से टक्कर के बाद उनकी नाव पलटने के बाद लापता हो गए थे। रविवार को दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में काकद्वीप घाट से गहरे पानी में मछली पकड़ने के लिए निकली एफबी परमिता नाम की नाव में 16 मछुआरे सवार थे। सोमवार तड़के एक बंगलादेशी नौसेना के जहाज ने उसे टक्कर मार दी, जिससे नाव पलट गई और बाद में डूब गई। उसी मालिक की एक और नाव हालांकि जो पीछे आ रही थी, उसके मछुआरों ने लहरों में बहने से पहले 11 साथी मछुआरों को बचा लिया। भारतीय तटरक्षक बल के गश्ती जहाजों ने घटना की जानकारी मिलने के बाद पांच लापता मछुआरों की तलाश के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

किसानों का कहना है कि यह संयंत्र पर्यावरण, जन स्वास्थ्य और भूमिगत जल स्रोतों के लिए घातक साबित होगा

किसानों, स्थानीय ग्रामीणों का नहीं थम रहा एथेनॉल संयंत्र का विरोध

श्रीगंगानगर, एजेंसी।

राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील क्षेत्र में स्थित गांव राठीखेड़ा के नजदीक एक निजी कंपनी द्वारा स्थापित किए जा रहे एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल संयंत्र को लेकर किसानों और स्थानीय ग्रामीणों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संयंत्र की क्षमता 40 मेगावाट बताई जा रही है और इसकी अनुमानित लागत करीब 450 करोड़ रुपये है। पिछले हफ्ते हुई व्यापक हिंसा के बाद राज्य सरकार ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने की सहमति जताई थी लेकिन संघर्ष समिति और विभिन्न किसान संगठनों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है।

किसानों का कहना है कि यह संयंत्र पर्यावरण, जन स्वास्थ्य और भूमिगत जल स्रोतों के लिए घातक साबित होगा। पिछले सप्ताह राठी खेड़ा क्षेत्र में प्लांट निर्माण को लेकर किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें कई लोग घायल हुए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद शनिवार की देर शाम हनुमानगढ़ में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और 11 सदस्यीय संघर्ष समिति के बीच समझौता वार्ता हुई।

वार्ता में सरकार ने आश्वासन दिया कि जब तक स्थानीय लोगों की आशंकाओं-जैसे पर्यावरणीय प्रभाव, स्वास्थ्य जोखिम और जल दोहन-का समुचित समाधान नहीं किया जाता और परियोजना की समीक्षा नहीं होती, तब तक निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। संघर्ष समिति ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई लेकिन बाद में स्पष्ट कर दिया कि वे सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे ताकि संयंत्र यहां स्थापित ही न हो सके।

किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि देश के अन्य हिस्सों में ऐसे एथेनॉल संयंत्रों के आसपास के इलाकों से लगातार प्रतिकूल रिपोर्ट्स आ रही हैं जो पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्याओं और अत्यधिक भूमिगत जल दोहन की ओर इशारा करती हैं। राठीखेड़ा के ग्रामीणों का कहना है कि वे इस संयंत्र को यहां नहीं लगने देंगे। यह हमारी जमीन, पानी और स्वास्थ्य को बर्बाद कर देगा। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपने वायदों से मुकरती है तो आंदोलन और तेज होगा। इसी क्रम में किसान संगठनों और संघर्ष समिति ने 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ में एक बड़ी महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया है। इस महापंचायत में प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा सीकर सांसद कॉमरेड अमराराम, पंजाबी लोक गायक कंवर ग्रेवाल सहित राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई किसान नेता शामिल होंगे।

महापंचायत की तैयारी के लिए हनुमानगढ़ जिले के साथ-साथ पड़ोसी श्रीगंगानगर जिले में भी गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। नुक्कड़ सभाएं और रैलियां आयोजित की जा रही हैं। आज श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर क्षेत्र में गांव बुधरवाली, तख्त हजारा, दूदाखीचड़ और चक सोहने वाला आदि गांवों में माकपा नेता पालाराम नायक, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष कौरसिंह सिधू ने जनसंपर्क किया।

रंधावा भाजपा में शामिल होने को कैप्टन की तारीफ कर रहे: धालीवाल

चंडीगढ़, एजेंसी।

पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने सोमवार को कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की हालिया तारीफ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रंधावा का बयान भाजपा में शामिल होने का रास्ता बनाने की कोशिश है। धालीवाल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अचानक तारीफ से कई गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने पूछा कि जब 2021 में कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था।

तो सुखजिंदर रंधावा ही सबसे आगे थे जो कैप्टन पर गुटका साहिब की कसम खाने के बावजूद ड्रग तस्करी की कमर तोड़ने में नाकाम रहने और हर घर में नौकरी देने का वादा पूरा न करने का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि आज रंधावा को यह साफ करना चाहिए कि तब कैप्टन सही थे या अब सही हैं।

असल में, रंधावा और कैप्टन दोनों ऐसे लोग हैं जो अपनी बात पर कायम नहीं रहते।

उन्होंने दावा किया कि सुखजिंदर रंधावा के बयान साफ तौर पर दिखाते हैं कि वह कांग्रेस पार्टी को डुबोकर भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार का इतिहास रहा है कि वे हमेशा सत्ता में रहने वालों के साथ रहे हैं, चाहे वह मुगल काल हो, ब्रिटिश काल हो, कांग्रेस का समय हो, या अब भाजपा का समय हो। उन्होंने कहा कि कैप्टन का परिवार सत्ता के बिना नहीं रह सकता।

मैं फॉर्म से बाहर नहीं हूं, लेकिन रन नहीं बन रहे है: सूर्यकुमार

टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, जब रन आने होंगे, तब आएंगे। मैं फॉर्म से बाहर नहीं हूं।

धर्मशाला,एजेंसी। भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी फॉर्म को लेकर कहा कि मैं नेट्स पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं। जब रन आने होंगे, तब आएंगे। मैं फॉर्म से बाहर नहीं हूं। तीसरे टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को कल रात सात विकेट से हराने के बाद संवाददाता सम्मेलन में सूर्यकुमार यादव, खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप कैसे वापसी करते हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण है। पिछली मैच में हमने काफी कुछ सीखा था, और आज हमने वही किया। (खराब फार्म के बारे में) मैं नेट्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं।

जब रन आने होंगे, तब आएंगे। मैं फॉर्म से बाहर नहीं हूं। यह अलग बात है कि रन नहीं आ रहे हैं। हम जीत का आनंद लेंगे, कल लखनऊ पहुंचने के बाद बैठेंगे और वहां से आगे की योजना बनाएंगे। प्लेयर ऑफ द मैच अर्शदीप सिंह ने कहा, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप सही तरह से अपनी योजना को नहीं निभा पाते हैं, वह पिछले मैच में हुआ था। आज मैं बेसिक्स पर टिका रहा और उसी से सफलता मिली। कुछ भी नहीं बदला, मैंने बस गेंद को सही एरिया में पिच किया और विकेट की मदद का इस्तेमाल किया।

ठंड में सीम और स्विंग दोनों थी। (हेंड्रिक्स का रिव्यू) सूर्या भाई थोड़ा सस्पेंस चाहते थे, इसी लिए शायद उन्होंने रिव्यू लेने में मदद की। मुझे पता था कि पैड पर लगने के तुरंत बाद ही वह आउट था। मेरी भतीजी यहां है वह दस महीने की है, मैं यह पुरस्कार उसे समर्पित करना चाहता हूं। वरुण चक्रवर्ती ने कहा, मुझे तो सच में इस मील के पत्थर (टी-20 में 50 विकेट) के बारे में पता नहीं था, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। शुरुआत में जब तेज गेंदबाज गेंद डाल रहे थे तो थोड़ा मूवमेंट मिल रहा था, कुछ सीम मूवमेंट था। लेकिन कुल मिलाकर परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। मैंने इतनी ठंड में कभी किसी मैदान पर नहीं खेला, इसलिए मुझे यह बेहद चुनौतीपूर्ण लगा। हमारी एक प्रॉपर बोलिंग मीटिंग हुई और बहुत ही ईमानदारी से बातचीत हुई। हमने पहचाना कि हमसे कहां गलती हुई और सही दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। इसका श्रेय मैनेजमेंट और गेंदबाजो को जाना चाहिए। यह एक दो-तरफा चर्चा थी और इसने सच में बहुत अच्छा काम किया। मैं बस अपनी ताकत पर टिके रहने का प्रयास कर रहा था।

सूर्यकुमार और गिल हमें विश्व कप में मैच जिताएंगे: अभिषेक

धर्मशाला,एजेंसी। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का मानना है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल जल्द ही फॉर्म में वापसी करेंगे और अपनी पारियों से आगे वर्ष फरवरी में होने वाले विश्वकप में भारत को जीत दिलायेंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में हुए तीसरे टी-20 एक बार फिर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (11 गेंद में 12 रन) और उपकप्तान शुभमन गिल (28 गेंद में 28 रन) बल्ले के साथ असफल रहने को लेकर अभिषेक ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैं एक बात सीधे कह सकता हूं कि ये दोनों भारत को विश्व कप में मैच जिताने जा रहे हैं।

उससे पहले अगले आने वाले मैचों में भी ये ऐसा करते हुए दिखेंगे। मैं इन दोनों खासकर शुभमन के साथ लंबे समय से खेलते आ रहा हूं, तो मुझे पता है कि ये क्या कर सकते हैं। मुझे गिल पर शुरुआत से ही भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जल्द ही उससे एक बड़ी पारी देखेंगे। इस मैच में जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में हर्षित राणा ने अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर भारत को बेहतरीन शुरुआत दी और सातवें ओवर तक उनके चार बल्लेबाज़ सिर्फ़ 30 के स्कोर पर पवेलियन में थे।

दोनों ने आपस में मिलकर 2-2 विकेट बांटे और इसके बाद स्पिनरों और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडरों ने मोर्चा संभाल लिया। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके तो हार्दिक पंड्या और शिवम् दुबे ने भी अनुशासित गेंदबाजी करते हुए 1-1 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवरों में मात्र 120 रन ही बना सकी।

अभिषेक ने भी भारतीय तेज गेंदबाजो की तारीफ करते हुए कहा कि तेज गेंदबाजो ने शुरुआती परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया, जिससे उनकी टीम शुरुआत में ही मैच में आगे हो गई थी।

उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने हमें शुरुआत दी, मुझे लगा कि मैच वहीं समाप्त हो गया था। पिच से तेज गेंदबाजो को मदद मिल रही थी और अगर यह एक हाई स्कोरिंग मैच होता तो दूसरी पारी में हमें भी रन बनाने में दिक्कतें होती। इसलिए पूरा क्रेडिट गेंदबाजो को जाता है। मैंने भी पिच और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ शॉट खेलें और यही हमेशा से मेरा प्लान रहता है।

मुझे पता था कि अगर मुझे सही शुरुआत मिलती है, तो मैच पावर प्ले में भी खत्म हो सकता है। अभिषेक ने कहा कि सर्दियों में होने वाले विश्व कप को देखते हुए टीम का यह प्रदर्शन बहुत अहम है। उन्होंने कहा, सलामी बल्लेबाजो और नए गेंद के गेंदबाजो से इस तरह की शुरुआत मिलना पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ाता है। टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है और माहौल बेहद सकारात्मक है।

भारत के नई गेंद के गेंदबाजों ने हमारे लिये मुश्किलें खड़ी की: माक्ररम

धर्मशाला,एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन माक्ररम ने तीसरे टी20 मैच में मिली हार के बाद कहा कि भारत के नयी गेंद के गेंदबाजों ने उनके लिये दिक्कतें खड़ी की और उनके बल्लेबाज तेजी से रन नहीं बना सके। भारत के अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने पहले चार ओवर के भीतर दक्षिण अफ्रीका के तीन विकेट उस समय निकाल दिये जब स्कोर बोर्ड पर सात रन ही टंगे थे। इन झटकों से माक्ररम की टीम उबर नहीं सकी और 117 रन बनाने के बाद सात विकेट से हार गई।

माक्ररम ने मैच के बाद कहा, उन्होंने सही जगहों पर गेंद डाली। अर्शदीप ने उम्दा गेंदबाजी की। उनके नयी गेंद के दोनों गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा,आपको अनुकूल हालात मिल सकते हैं लेकिन आखिर में गेंदबाजों को सही जगहों पर गेंद डालनी होगी और उन्होने वही किया। उन्हें इसका श्रेय दिया जाना चाहिये। पहली गेंद से ही उन्होंने हमारे लिये मुश्किलें खड़ी की। माक्ररम ने स्वीकार किया कि हालात चुनौतीपूर्ण थे लेकिन यह भी कहा कि टीम को इसके अनुकूल ढलना होगा। उन्होंने कहा, हालात कठिन थे लेकिन हमें इसके अनुरूप ढलना होगा। मौसम ठंडा था जिसका असर पड़ा लेकिन इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिये।

बीसीसीआई को एनएसएफ के रूप में मान्यता नहीं: मांडविया

नई दिल्ली,एजेंसी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) नहीं है। उन्होंने लंबे समय से चली आ रही स्थिति को दोहराया जिसके अगले साल नए राष्ट्रीय खेल संचालन अधिनियम के लागू होने के बाद बदलने की उम्मीद है। मांडविया तृणमूल कांग्रेस की कोलकाता दक्षिण की प्रतिनिधि माला रॉय के एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

रॉय ने पूछा था कि क्या सरकार बीसीसीआई जैसे बड़े खेल संगठनों और पैसे की कमी से जूझ रहे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को 'ठीक से और सुचारू रूप से चलाने' के लिए उनका नियंत्रण अपने हाथ में लेने का इरादा रखती है। मांडविया ने दोहराया कि एनएसएफ से 'अच्छे प्रबंधन तरीकों' का पालन करने की उम्मीद की जाती है।

मांडविया ने कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) के रूप में मान्यता नहीं मिली है। राष्ट्रीय खेल संचालन अधिनियम इस साल अगस्त में पारित हुआ था और इसके नियम जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे। मांडविया ने अगले साल की शुरुआत में इस अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने का वादा किया है। इसमें एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) का प्रावधान है जो जवाबदेही की एक सख्त प्रणाली बनाएगा और सभी एनएसएफ को केंद्र सरकार से कोष पाने के लिए एनएसबी से मान्यता लेनी होगी। बीसीसीआई अब तक एक मान्यता प्राप्त एनएसएफ नहीं है क्योंकि यह सरकार के कोष पर निर्भर नहीं है।

हालांकि जब नया कानून लागू होगा तो बीसीसीआई को खुद को एनएसएफ के तौर पर पंजीकृत कराना होगा क्योंकि क्रिकेट एक ओलंपिक खेल बन गया है जो 2028 खेलों में टी20 प्रारूप में पदार्पण करने वाला है। मंत्रालय ने बोर्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के मामले में पहले ही कुछ राहत दी है जो नए अधिनियम के तहत एनएसएफ पर लागू होंगे। इसने अधिनियम में आरटीआई से संबंधित प्रावधान में संशोधन किया है और केवल उन्हीं महासंघों को इसके दायरे में रखा है जो सरकारी अनुदान और सहायता पर निर्भर हैं।

सूचना का अधिकार कानून बीसीसीआई के लिए एक मुश्किल मुद्दा रहा है जिसने लगातार इसके दायरे में आने का विरोध किया है क्योंकि बोर्ड अधिकांश अन्य एनएसएफ की तरह सरकारी कोष पर निर्भर नहीं है।

हर भारतीय खिलाड़ी को कम से कम दो विजय हजारे मैच खेलने होंगे

नई दिल्ली,एजेंसी। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के मौजूदा खिलाड़ियों के लिये 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम दो वनडे मैच खेलना अनिवार्य कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 मैच (19 दिसंबर) और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे (11 जनवरी , 2026) के बीच तीन सप्ताह से अधिक का अंतर है और बोर्ड चाहता है कि सभी सीनियर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलें।

अजित अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सभी को यह निर्देश दे दिया है। इस साल की शुरूआत में आस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला में हार के बाद यह सिफारिश की गई थी। इसमें हर प्रारूप में घरेलू क्रिकेट पर अधिक जोर देने के लिये कहा गया था। विराट कोहली और रोहित शर्मा टूर्नामेंट के लिये अपनी उपलब्धता की सूचना दे चुके हैं। वहीं सीनियर खिलाड़ी शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव को अपनी अपनी टीमों के लिये कम से कम दो मैच खेलने के लिये कहा जा सकता है।

बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, विजय हजारे ट्रॉफी के छह दौर 24 दिसंबर से खेले जाने हैं। यह खिलाड़ियों और उनके प्रदेश संघों पर निर्भर करता है कि वे कौन से दो दौर खेलना चाहते हैं।

बिजनेस

भेल ने केंद्र सरकार को सौंपा 109 करोड़ रुपये का लाभांश

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) ने केंद्र सरकार को 2024-25 के लिए 109 करोड़ रुपये से अधिक के लाभांश का चेक सौंपा है। भारी उद्योग मंत्रालय की एक सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भेल ने आज यहां केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को लाभांश का चेक सौंपा।

सोने का आयात नवंबर में 59 प्रतिशत घटा, चांदी में 125 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली,एजेंसी। सोने के आयात मूल्य में नवंबर में 59 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी जबकि चांदी में 125 प्रतिशत की तेज वृद्धि रही। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में 402.1 करोड़ डॉलर का सोना आयात किया गया।

मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड भारत को विश्व का डाटा केंद्र बना सकता है: गोयल

नई दिल्ली,एजेंसी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के दौर में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव को कायाकल्प बताते हुए कहा कि भारत में बिजली की दरें अब चीन जैसे अपने प्रतिस्पर्धी देशों के स्तर पर आ गयी हैं और देश में एक मजबूत तथा एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड का विकास भारत को डाटा का वैश्विक केंद्र बना सकता है। गोयल ने देश के ऊर्जा क्षेत्र में मोदी सरकार के ग्यारह-साढ़े ग्यारह वर्ष के 'कायाकल्प' की जानकारी देते हुए कहा, हमारे पास आज एक राष्ट्रीय बिजली ग्रिड है जो दुनिया में सबसे अच्छी ग्रिड प्रणालियों में एक है। अमेरिका और यूरोप में भी एकीकृत राष्ट्रीय विद्युत पारेषण ग्रिड नहीं है।

उन्होंने कोयला, गैस और नवीकरणीय स्रोतों से देश में बिजली उत्पादन की क्षमता में इस दौरान उल्लेखनीय वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में बिजली की आपूर्ति , आपूर्ति की विश्वसनीयता और दर के मामले में पूरे देश में एक बड़ा बदलाव आया है। देश बिजली की कमी वाले देश की जगह आज इफरात वाले देश की स्थिति में पहुंच गया है। गोयल ने कहा कि बिजली की कमी 2013 में 4.2 प्रतिशत से घटकर 2025 में 0.1 प्रतिशत हो गई है और यह कमी भी स्थापित क्षमता के कारण नहीं बल्कि तकनीकी कारण से है।

उन्होंने बताया कि एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड के निर्माण से भारत व्यस्त समय में 2,50,000 मेगा वाट की रिकॉर्ड मांग को पूरा करने में सक्षम हुआ है। उन्होंने बताया कि पीएम-उदय योजना के तहत किए गए सुधारों से बिजली वितरण क्षेत्र मजबूत हुआ है और डिस्कॉम का बकाया 2022 में 1.4 लाख करोड़ रुपये से घटकर 2025 में 6,500 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने 2047 तक ग्रीन हाइड्रोजन, कोल गैसीफिकेशन प्रौद्योगिकी और छोटी मॉड्यूलर परमाणु बिजली इकाइयों सहित हरित ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि भरोसे मंद बिजली आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत एकीकृत ग्रिड की बदौलत भारत विश्च का डाटा केंद्र बन सकता है।

उन्होंने भारत में बिजली की वाणिज्यिक दरें चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बहुत होने के सुझाव से असहमति जताते हुए कहा कि भारत में बिजली की वाणिज्यिक दरें तुलनात्मक रूप से अब प्रतिस्पर्धी देशों के समकक्ष कही जा सकती हैं। गोयल ने कहा कि 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना और जीवाश्म ईंधन के आयात में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी लाना है।

उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत लगभग 20 लाख घरों में छतों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के शब्दों को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार जनता को सशक्त बना रही है तथा कोयले पर उच्चाधिकार समिति की कई सिफारिशें विचाराधीन हैं, जिनमें कोयले की खोज और खनन में तेजी लाना और कोयले के गैसीकरण को गति देना शामिल है।

जीएसटी में कटौती से रिटेल क्रेडिट मार्केट को मिला बढ़ावा

ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन में उछाल : रिपोर्ट

नई दिल्ली। भारत में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) सुधार से रिटेल क्रेडिट बाजार में तेजी आई है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में क्रेडिट मार्केट इंडिकेटर (सीएमआई) का स्कोर 98 से बढ़कर 99 हो गया, जो इस बात को दर्शाता है कि लोग अब ज्यादा आसानी से कर्ज ले पा रहे हैं। यह बढ़ोतरी कर्ज की कीमतों में कमी और उपभोक्ताओं की खरीदारी में बढ़े हुए भरोसे को दिखाती है।

ट्रांसयूनियन सीआईबीएल की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदरा ऋण की बढ़ती मांग से उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और बाजार में आशा का माहौल बना है। सीएमआई का डिमांड पिलर 2025 के सितंबर तिमाही में 93 से बढ़कर 95 हो गया। इसका मुख्य कारण वाहन वित्त (ऑटो लोन) और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु (कंज्यूमर ड्यूरेबल्स) की बढ़ती मांग रही। 2025 के अक्टूबर में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए लोन की मांग 128 से बढ़कर 189 हो गई। वहीं, दो पहिया वाहनों के लिए लोन की मांग 249 से बढ़कर 272 हो गई। साथ ही, ऑटो लोन (कार लोन) की मांग भी 115 से बढ़कर 133 हो गई।

रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 की तीसरी तिमाही में सीएमआई के आपूर्ति पक्ष का स्कोर 91 से बढ़कर 97 हो गया। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से गोल्ड लोन और कंज्यूमर लोन में हुई है। होम लोन, ऑटो लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन की आपूर्ति में भी सकारात्मक बदलाव देखा गया है, हालांकि पिछले साल इनमें गिरावट आई थी।

वहीं तिमाही के दौरान कुल लोन आपूर्ति में अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा 61 प्रतिशत रहा। ट्रांसयूनियन सीआईबीएल जैन के एमडी और सीईओ भावेश जैन ने कहा, 'यह एक अच्छा अवसर है कि लोन देने वाली कंपनियां इन नई श्रेणियों के उधारकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बनाएं।' नए क्रेडिट उधारकर्ताओं की संख्या में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और 35 वर्ष से कम उम्र के उधारकर्ता में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

रुपये के दबाव में लुढ़के शेयर बाजार

मुंबई,एजेंसी। रुपये में लगातार जारी गिरावट के दबाव में घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 54.30 अंक (0.06 प्रतिशत) फिसलकर 85,213.36 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 19.65 अंक यानी (0.08 प्रतिशत) गिरकर 26,027.30 अंक पर रहा। रुपये पर आज भारी दबाव रहा। बीच कारोबार में यह पहली बार 90.80 रुपये प्रति डॉलर के निचले स्तर तक लुढ़क गया। इससे शेयर बाजारों में निवेश धारणा कमजोर रही।

बाजार में आज शुरुआती गिरावट रही। दोपहर बाद कुछ देर के लिए सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान को छूने में कामयाब रहे, हालांकि अंत में गिरावट में लाल निशान में ही बंद हुए। बड़ी और मझौली कंपनियों पर जहां दबाव रहा, वहीं छोटी कंपनियों में निवेशकों ने लिवाली की। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक में 0.08 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी जबकि स्मॉलकैप-100 में 0.21 प्रतिशत की तेजी देखी गयी। च्वॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के विश्लेषक अमृता शिंदे और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियर सर्विसेज में वेल्थ मैनेजमेंट के अनुसंधान प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने बताया कि वृहद बाजार में निवेशकों ने चुनिंदा कंपनियों में खरीदारी की।

एनएसई में कुल 3,237 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ जिनमें 1,665 के शेयर हरे निशान में और 1,468 के लाल निशान में बंद हुए। वहीं, 104 कंपनियों के शेयर दिन भर के उतार-चढ़ाव के बाद अंत में अपरिवर्तित रहे।

ऑटो, फार्मा और स्वास्थ्य सेक्टरों में ज्यादा गिरावट रही। मीडिया, एफएमसीजी, आईटी, बैंकिंग, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और रसायन समूहों के सूचकांक हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स की 30 में से 15 कंपनियों के शेयर हरे निशान में बंद हुए। हिंदुस्तान यूनीलिवर का शेयर 1.42 प्रतिशत चढ़ा।

ट्रेंट में 0.79 फीसदी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में 0.70, एशियन पेंट्स में 0.53 और टाटा स्टील तथा इंफोसिस दोनों में 0.52 फीसदी की तेजी रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 1.94 फीसदी गिरा। बजाज फिनसर्व का शेयर 0.79 प्रतिशत, मारुति सुजुकी 0.71, अडानी पोर्ट्स का 0.66 और भारती एयरटेल का 0.55 प्रतिशत टूट गया।

वैश्विक बाजारों में एशिया में हांगकांग का हैंगसेंग 1.34 फीसदी, जापान का निक्केई 1.31 फीसदी और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.55 फीसदी गिरकर बंद हुआ।

थोक मुद्रास्फीति की दर नवंबर में लगातार दूसरे महीने शून्य से नीचे

नई दिल्ली,एजेंसी। खाने-पीने की चीजों और ईंधन एवं बिजली वर्ग की वस्तुओं की कीमतों में सालाना आधार पर गिरावट के कारण थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर नवंबर में शून्य से 0.32 प्रतिशत नीचे दर्ज की गयी। देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में नयी पीढ़ी के सुधारों के बाद यह लगातार दूसरा महीना है जब थोक मुद्रास्फीति शून्य से नीचे रही है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में थोक मुद्रास्फीति शून्य से 1.21 प्रतिशत कम थी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि नवंबर में खाद्य वस्तुओं की थोक मुद्रास्फीति शून्य से 2.60 प्रतिशत कम रही है जो अक्टूबर में शून्य से 5.04 प्रतिशत नीचे रही है। नवंबर 2024 की तुलना में नवंबर 2025 में प्याज की थोक कीमत 64.70 प्रतिशत, आलू की 36 प्रतिशत, सब्जियों की 20.23 प्रतिशत और दालों की 15.21 प्रतिशत कम हुई है।

गेहूं, धान और फलों के दाम में भी सालाना आधार पर गिरावट रही है। खाने-पीने की चीजों की अलावा थोक में ईंधनों की कीमतों में भी भारी गिरावट देखी गयी है। कच्चा तेल के दाम 13.92 प्रतिशत कम हुए। पेट्रोल 1.75 फीसदी और डीजल 1.64 फीसदी सस्ता हुआ। रसोई गैस की कीमत में 12.78 फीसदी की गिरावट आयी है। अन्य वस्तुओं की कीमतें भी या तो एक साल पहले के मुकाबले कम हुई हैं या उनकी वृद्धि दर कम रही है।

इससे पहले 12 दिसंबर को जारी खुदरा महंगाई के आंकड़ों में भी इसकी दर 0.71 प्रतिशत रही थी। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गत 05 दिसंबर को जारी मौद्रिक नीति समीक्षा बयान में चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान घटाकर दो प्रतिशत कर दिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बयान जारी करते हुए कहा था कि चालू वित्त वर्ष की 31 दिसंबर को समाप्त हो रही तीसरी तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति 0.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं, अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति 3.9 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में चार प्रतिशत रहने की संभावना है।

'पालकी पे होके सवार' गाने पर अंकिता लोखंडे ने किया रिवीलिंग डांस

मुंबई। 80-90 दशक के गाने कुछ ऐसे होते थे, जिन्हें आज भी दर्शक बड़ा पसंद करते हैं और सुनते भी हैं। टेलीविजन अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने उस दौर को याद करते हुए एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया।

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में अंकिता अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के मशहूर गाने 'पालकी पे होके सवार' पर शानदार एक्सप्रेशन के साथ डांस कर रही हैं।

वीडियो पोस्ट कर अंकिता ने लिखा, 80-90 के दशक के गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। उन्होंने माधुरी दीक्षित को एक एहसास बताते हुए कहा कि क्या आज की पीढ़ी को वो आवाज मिलेगी, पर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है।

अंकिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि उन्होंने उस स्वर्णिम युग को देखा और जिया, भले ही बचपन में। उस समय से ही उन्होंने सपने देखना और उनसे प्रेरणा लेना शुरू किया था और आज भी सीख रही हैं।'

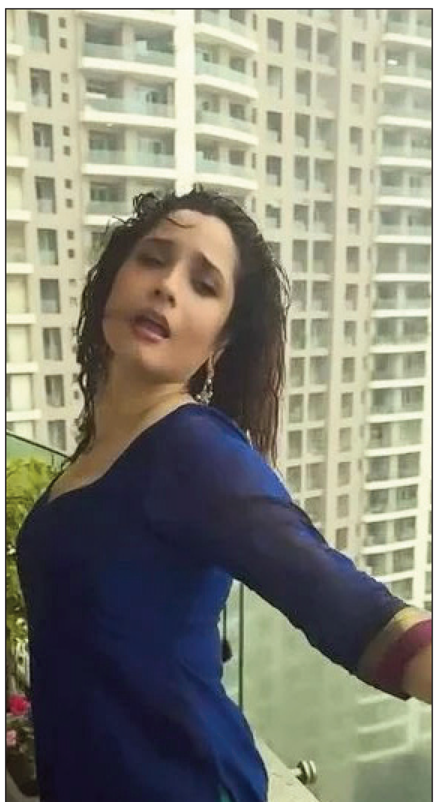

पालकी पे होके सवार' गाना फिल्म 'खलनायक' में फिल्माया गया था। गाने को अल्का यागनिक ने गाया था और इसके लिरिक्स आनंद बक्शी ने लिखे थे, जबकि संगीत लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर ने तैयार किया था। वहीं, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से गाने की खूबसूरती बढ़ा दी थी। इस गाने को लोग आज भी पसंद करते हैं।

फिल्म खलनायक 1993 में रिलीज हुई थी और इसे सुभाष घई ने निर्देशित किया था। फिल्म में माधुरी दीक्षित के अलावा, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में संजय दत्त ने खलनायक की भूमिका अदा की थी, जिसमें उनका डायलॉग 'नायक नहीं खलनायक हूं मैं' काफी फेमस हुआ था। दर्शकों ने अभिनेता का ये किरदार काफी पसंद किया था।

रानी चटर्जी को 'सईयां' से है शिकायत, आम्रपाली के गाने पर बनाई धांसू रील

मुंबई। भोजपुरी सिनेमा तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां नए-नए गाने और फिल्में रिलीज होती हैं, तो वहीं कलाकार एक-दूसरे के गाने पर डांस कर सोशल मीडिया पर उन्हें सपोर्ट करते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ अभिनेत्री रानी चटर्जी ने किया।

रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में अभिनेत्री दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली के गाने 'सईयां जी सेल्फिश' के बोल पर शानदार एक्सप्रेशन देती नजर आ रही हैं। रानी चटर्जी गाने के हर बोल पर अपने चेहरे के हाव-भाव से कमाल कर रही हैं। अभिनेत्री ने वीडियो को पोस्ट करते हुए मजेदार अंदाज में लिखा, 'आप जले हुए सैया ग्रीस निकले। आम्रपाली की आवाज और मेरे चेहरे के इस कॉम्बो के बारे में क्या कहना।'

अभिनेत्री की ये पोस्ट उनके प्रशंसकों को काफी पसंद आ रही है। वे कमेंट सेक्शन पर उनके एक्सप्रेशन की तारीफ कर रहे हैं और इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

गाना 'सईयां जी सेल्फिश' की बात करें तो इसे दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली ने गाया है। लिरिक्स श्याम देहाती ने लिखे हैं और म्यूजिक साजन मिश्रा ने तैयार किया है। गाने में आम्रपाली के साथ एजाज अहमद नजर आ रहे हैं।

रानी चटर्जी की बात करें तो वे अभिनय में एक्टिव रहने के साथ-साथ सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव रहती हैं। उनके फैंस उनके डांस और एक्टिंग के साथ-साथ ऐसे मजेदार रील्स को भी खूब पसंद करते हैं।

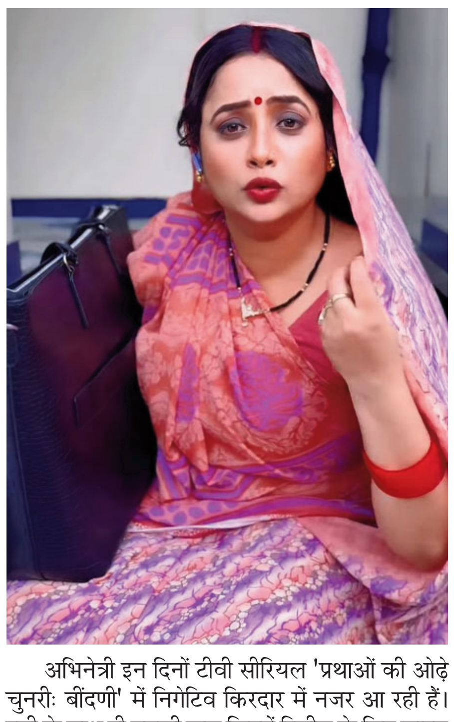

अभिनेत्री इन दिनों टीवी सीरियल 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरीः बींदणी' में निगेटिव किरदार में नजर आ रही हैं। इसी के साथ ही उनकी कुछ फिल्में रिलीज के लिए लाइन पर हैं, जिनमें 'परिणय सूत्र' और 'यूपी वाली-बिहार वाली' शामिल हैं।

'धुरंधर' की सक्सेस पर निर्माता-निर्देशक सुभाष घई का सवाल, 'क्या जरूरी है, मेकर्स, कंटेंट या स्टार्स?'

मुंबई। फिल्म निर्देशक और निर्माता सुभाष घई बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही फिल्मों पर अपनी राय देते हैं। अब उन्होंने फिल्म 'धुरंधर' को लेकर कुछ ऐसी बात कही है, जो बड़े फिल्मी सितारों को थोड़ी चुभ सकती है। निर्माता ने फिल्म के अच्छे कंटेंट और मेकर्स पर फोकस करने की बात कही है, बड़े स्टार्स पर नहीं।

सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया और अच्छे कंटेंट, मेकर्स और स्टार्स की बात की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मैंने कल कोमल नाहटा से पूछा कि अगर 'धुरंधर', 'सैयारा' और 'लालो' जैसी फिल्मों को दर्शक बहुत पसंद करें, तो ज्यादा क्या काम करता है? कंटेंट या मेकर्स या स्टार्स? उन्होंने मुझे तुरंत जवाब दिया कि कंटेंट और मेकर्स। स्टार्स तो सोने पर सुहागा हैं।

निर्माता ने आगे लिखा, ''अगर स्टार्स पहले है तो हम क्या सीखते हैं? क्या अच्छे मेकर्स के साथ सही एक्टर्स के बजाय स्टार्स के पीछे भागना सही है। 80-90 के दशक के सिनेमा में भी ऐसा ही था।

निर्माता के पोस्ट पर यूजर्स भी रिएक्ट कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि फिल्म की अच्छी कहानी और किरदार ही किसी फिल्म को अच्छा बनाते हैं। एक यूजर ने लिखा, 'मिस्टर धर कितने क्रिएटिव दिमाग वाले हैं। यह फिल्म ओरिजिनल काम करने की ताकत का सबूत है।'

'धुरंधर' के रिलीज के बाद से भी फिल्म की स्टारकास्ट और उनकी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ हो रही है, ना कि मेकर्स और कंटेंट की। 80 से 90 के दशक में भी जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती थीं, उनमें भी फिल्म की लीड कास्ट की तारीफ होती थी, न कि निर्देशक, राइटर या फिर पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों की।

'धुरंधर' घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है।

विदेश

चिली के नए राष्ट्रपति चुने गए जोस एंटोनियो कास्ट

सैंटियागो। जोस एंटोनियो कास्ट चिली के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। चुनाव अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कास्ट ने राष्ट्रपति पद के दूसरे चरण के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है।

बीजिंग ने जापान के पूर्व सैन्य अधिकारी को निशाने पर लिया

बीजिंग/टोक्यो। चीन-जापान के बीच बिगड़े संबंधों में तल्खी और बढ़ गई है। अब बीजिंग ने सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ शिगेरू इवासाकी के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। वहीं जापानी मीडिया ने इसे प्रतीकात्मक प्रतिबंध बताया है, जो इस साल ताइवान की कैबिनेट के सलाहकार के तौर पर उनकी नियुक्ति का जवाब है।

अल्बनीज नहीं रखते नेतन्याहू के बयान से इत्तेफाक, फिलिस्तीन को लेकर अपनी बात पर कायम

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान से असहमति जताई जिसमें उन्होंने (नेतन्याहू) बोंडी बीच नरसंहार को फिलीस्तीन से जोड़ा।

प्रधानमंत्री अल्बनीज ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस सुझाव को खारिज कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने से आतंकवादी हमला हुआ, जिससे 'यहूदी विरोधी आग में घी डाला गया।

एबीसी के 7.30 रिपोर्ट (एक ऑस्ट्रेलियाई सप्ताह-रात्रि टेलीविजन करेंट अफेयर्स कार्यक्रम) में पहुंचे अल्बनीज ने नेतन्याहू के बयान को लेकर पूछे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। नेतन्याहू का आरोप था कि अल्बनीज ने यहूदी-विरोध को फैलने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया और उन्होंने 'कमजोरी को

कमजोरी से और तुष्टीकरण को और ज्यादा तुष्टीकरण से बदल दिया है।' जब उनसे पूछा गया कि क्या वह फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने और बोंडी में हुए नरसंहार के बीच किसी संबंध को स्वीकार करते हैं, तो अल्बनीज ने कहा, ' नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता और ज्यादातर दुनिया दो-राज्य समाधान को ही मध्य पूर्व में आगे बढ़ने का रास्ता मानती है।'

अल्बनीज ने शांति व्यवस्था बनाए रखने को अपना प्रमुख कर्तव्य बताया। उन्होंने कहा, 'मुझसे क्या उम्मीद की जाती हैः इस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री के तौर पर, देश को एक साथ लाना, एकता को बढ़ावा देना... यह कहना कि यह राष्ट्रीय एकता का क्षण है जहां हमें एक साथ आने की जरूरत है।' रविवार को सिडनी के बोंडी बीच पर आठ दिवसीय हनुक्का पर्व का पहला दिन मनाने पहुंचे निहत्थे यहूदियों पर दो दहशतगर्दों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की।

जिसकी पूरी दुनिया ने सख्त शब्दों में निंदा की। देर शाम नेतन्याहू ने कहा कि तीन महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को लिखा था कि आपकी नीति यहूदी-विरोधी भावना की आग में तेल डाल रही है।उन्होंने वो पत्र अगस्त में एंथनी अल्बनीज को भेजा था, जब कैनबरा ने फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की घोषणा की थी। नेतन्याहू ने दक्षिणी इजरायल में एक कार्यक्रम के दौरान टेलीविजन पर सार्वजनिक संबोधन में कहा कि यहूदी विरोध एक ऐसा कैंसर है जो तब फैलता है जब नेता चुप रहते हैं और कार्रवाई नहीं करते।

इससे पहले, इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे घृणित बताया। उन्होंने कहा कि सिडनी में हमारे बहनों और भाइयों पर एक बहुत ही क्रूर हमला किया गया। यह लोग बोंडी बीच पर हनुक्का की पहली मोमबत्ती जलाने गए थे। उन्होंने कहा कि इस क्षण पूरे इजरायल देश की धड़कन रुक सी गई है। हम घायल हुए लोगों के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और जिनकी जान गई, उनके लिए भी।

कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिका में भारतीय प्रवासियों से की एकजुटता की अपील

शिकागो। भारतीय मूल के कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने एक बार फिर अमेरिका में रह रहे भारतीयों से एकजुटता और आवाज उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय अमेरिकियों को अपनी आवाज उठाकर, गठबंधन बनाकर और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाकर बढ़ती कट्टरता का सामना करना चाहिए। उन्होंने सलाह भी दी कि चुप रहने से सिर्फ समुदाय कमजोर होगा।शिकागो में इंडिया अब्रॉड डायलॉग में कृष्णमूर्ति ने कहा, "हम अभी ऐसे दौर में हैं जहां भारत विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं और अगर राजनीतिक हिंसा के साथ इसकी बढ़ोतरी होगी, तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा।"

उन्होंने अपनी स्पीच में उनके खिलाफ फैल रही नफरत भरी बातों का भी जिक्र किया। कृष्णमूर्ति ने कहा कि "फ्लोरिडा के एक चुने हुए अधिकारी ने मुझे देश से निकालने की बात कही। उसने मुझे विदेशी कब्जा करने वाला कहा। मैंने उससे कहा कि तुम बस मुझे राजा कहो और मैं तुम्हें नस्लवादी कहूंगा।'

कृष्णमूर्ति ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए तीन जरूरी बातों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'पहली बात, हमें आवाज उठानी होगी। चुप रहने से हिंसा और विरोध कम नहीं होता है। दूसरा, जब किसी और के खिलाफ कट्टरता, भेदभाव और नफरत हो, तब भी आपको आवाज उठानी चाहिए।' तीसरी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात कही। उन्होंने सभी समुदायों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। उनका कहना है कि हमें दूसरे समुदायों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, जिससे समुदाय में मजबूती और एकता बढ़े।

सिडनी मास शूटिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े गन कानून सुधार की तैयारी

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एंटी-सेमेटिक मास शूटिंग ने पूरी दुनिया को थर्रा दिया है। उत्सव मनाने के लिए जुटे यहूदियों पर बंदूकधारी बाप-बेटे ने ताबड़तोड़ गोलियां दागीं। 8, 9 और फिर 16 मारे गए। संख्या और बढ़ भी सकती है। बंदूकधारियों ने 10 साल की बच्ची से लेकर 82 साल के बुजुर्ग तक को नहीं छोड़ा। इस सामूहिक हत्या ने ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया के पोर्ट आर्थर नरसंहार की याद दिला दी है और अल्बनीज सरकार गन कानून सुधार को लेकर तत्पर है।

द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार, सोमवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद जारी एक बयान में, प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज, राज्य के प्रीमियर और मुख्यमंत्रियों ने कहाः "नेशनल कैबिनेट ने यहूदी-विरोधी भावना, नफरत, हिंसा और आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प लिया और आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने, सामाजिक एकता, संसाधन और बयानबाजी पर राष्ट्रीय समन्वय के प्रति ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता पर जोर दिया ताकि समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने सहमति जताई कि ₹गन कानून सुधार पर तुरंत मजबूत, निर्णायक और केंद्रित कार्रवाई की जरूरत है, जिसमें नेशनल फायरआर्म्स एग्रीमेंट पर फिर से बातचीत करना शामिल है, जिसे पहली बार 1996 की पोर्ट आर्थर त्रासदी के बाद स्थापित किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आज के बदलते सुरक्षा माहौल में यह जितना संभव हो उतना मजबूत बना रहे।'

बांग्लादेश में हिरासत में लिया गया एक और पत्रकार

ढाका। बांग्लादेश में जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, देश में हिंसा और तनाव का माहौल बढ़ रहा है। आए दिन हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पत्रकार भी वहां सुरक्षित नहीं हैं। पत्रकारों के अधिकार का भी हनन हो रहा है। बांग्लादेश के स्थानीय मीडिया ने सोमवार को बताया कि वरिष्ठ पत्रकार अनीस आलमगीर को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) की डिटेक्टिव ब्रांच (डीबी) ने खास मुद्दों से जुड़ी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।

हाल के कुछ दिनों में बांग्लादेश में पत्रकारों पर हमले की घटना में बढ़ोतरी ने देश में प्रेस की आजादी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। हफ्ते भर में ऑन-ड्यूटी पत्रकार रिसान पर हमले का मामला सामने

आया। ढाका-8 से निर्दलीय उम्मीदवार और इकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान बिन हादी को दो बदमाशों ने दिन दहाड़े सिर पर गोली मार दी। इसके बाद 12 दिसंबर की दोपहर को रिसान ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (डीएमसीएच) में हादी पर हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, तभी छात्र से नेता बने हादी के समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया।

जुलाई की शुरुआत में, बाहर से आए 88 पत्रकारों, लेखकों, शोधकर्ताओं, कल्चरल और राइट्स एक्टिविस्ट्स के एक समूह ने यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में 'पत्रकारों पर लगातार टॉर्चर और बोलने की आजादी को दबाने' पर गंभीर चिंता जताई थी।इस महीने की शुरुआत में, कई जाने-माने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने बांग्लादेश में मानवाधिकार की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता जताई।

विशेषज्ञों ने दावा किया कि मानवाधिकारों के उल्लंघन बढ़ रहे हैं और राजनीतिक बदला लेने के लिए झूठे और मनगढ़ंत शिकायतों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।कनाडा के थिंक टैंक संगठन 'ग्लोबल सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस (जीसीडीजी)' ने 'बांग्लादेश इन क्राइसिसः ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी' नाम से एक वर्चुअल इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किया।